छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg No-CHHHIN/2020/87351

डाक पंजीयन क्र. 046/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 06 अंक - 68 बैकुंठपुर, मंगलवार 09 दिसंबर 2025 पृष्ठ -8 मूल्य -1

www.cgfrontline.com

कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ किया बैठक

छ.ग.फ्रंटलाइन

एमसीबी। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में अर्हता 01 जनवरी 2026 के संबंध में चलाये जा रहे निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है एवं उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में Enumeration form Uncollectable (Death, Permanent Shifting, Absent) की जानकारी के संबंध में उपस्थित प्रतिनिधियों से चर्चा किया गया। विधानसभा क्षेत्र 01 भरतपुर-सोनहत एवं 02 मनेंद्रगढ़ के जिन मतदान केंद्रों में Enumeration form Uncollectable है, उनकी सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिदार के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि आप सूची अनुसार मतदान केंद्रों में निरीक्षण कर

मतदाताओं का सत्यापन करा लें, ताकि पता चल सके कि BLO के द्वारा सही मैपिंग किया गया है या नहीं। सभी BLO को निर्देशित करने हेतु आग्रह किया गया ताकि यह सत्यापित हो सके कि सूची अनुसार मतदाता जो Uncollectable form कैटेगरी में मार्क हुए हैं वह सही है या नहीं। विधानसभा क्षेत्र 01 भरतपुर-सोनहत में 14034 मतदाता तथा 02 मनेंद्रगढ़ में 18,035 मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में political दलों के साथ हुई बैठक संपन्न। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में अर्हता 01 जनवरी 2026 के संबंध में चलाये जा रहे निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है एवं उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में Enumeration form Uncollectable (Death, Permanent Shifting, Absent) की जानकारी के संबंध में उपस्थित प्रतिनिधियों से चर्चा किया गया। विधानसभा क्षेत्र 01 भरतपुर-सोनहत एवं 02 मनेंद्रगढ़ के जिन मतदान केंद्रों में Enumeration form Uncollectable है, उनकी सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिदार के द्वारा राजनीतिक के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि आप सूची अनुसार मतदान केंद्रों में निरीक्षण कर मतदाताओं का सत्यापन करा लें ताकि पता चल सके कि BLO के द्वारा सही मैपिंग किया गया है या नहीं। सभी BLO को निर्देशित करने हेतु आग्रह किया गया ताकि यह सत्यापित हो सके कि सूची अनुसार मतदाता Uncollectable की श्रेणी में मार्क हुए हैं। अतः ऐसे मतदाताओं को गणना फार्म भरकर प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्ण होने पर BLO के पास जमा कर दें। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति, Enumeration form डिजिटाइजेशन की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में आज 11 बजे तक 144161 (99.95प्रतिशत) एवं 02 मनेंद्रगढ़ में 137067 (99.5प्रतिशत) फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष फार्मों को भी 16 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर के द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों से SIR के संबंध में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो साझा करने हेतु आग्रह किया गया। प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि मनेंद्रगढ़ के मतदान केंद्र क्रमांक 04 के कुछ मतदाताओं के नाम में पति-पत्नी का नाम एक जैसा दर्ज है। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने साझा की। कलेक्टर ने ऐसे मतदाताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि त्रुटि सुधार किया जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने सवाल किया कि किसी मतदाता का 2025 में अलग और 2003 में अलग नाम दर्ज है, तो उसका संशोधन कैसे होगा और आधार किस वर्ष का लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी ने बताया कि फॉर्म 8 भरें और आधार 2025 की मतदाता सूची को माना जाएगा। वहीं कलेक्टर ने भरतपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 32, 33, 34 और 35 को अच्छे से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इन मतदान केंद्रों में 631 लोग Uncollectable चिह्नित हैं। इस बैठक में आशीष कुमार मजूमदार जिला महामंत्री, सुरेश यादव, कांग्रेस से राजकुमार केशरवानी, हाफिज मेनन, आम आदमी पार्टी से विकास पाण्डेय, कासिम उमर के साथ सतीश द्विवेदी, उपेन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक

छ.ग.फ्रंटलाइन

एमसीबी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर पंचायत खोंगापानी कार्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हेतु निकाय के जनप्रतिनिधियों, बीएलए, बीएलओ तथा अधिकारी/कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने चल रहे पुनरीक्षण कार्य की महत्ता पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता की आधारशिला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों तथा बीएलए को सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए स्वच्छ एवं

त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग देने की अपील की। साथ ही बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई तथा कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण एवं सटीक पुनरीक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन), मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अधीक्षक (सामान्य निर्वाचन), प्रोग्रामर, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदगण, राजनीतिक दलों के बीएलए, तथा संबंधित मतदान केंद्रों के बीएलओ उपस्थित रहे।

उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत नवसाक्षर परीक्षा का निरीक्षण

एमसीबी। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान 2025-26 के तहत नवसाक्षर शिक्षार्थियों के लिए आयोजित परीक्षा का निरीक्षण सरगुजा संभाग के सहायक संचालक श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। श्री गुप्ता आज मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड मनेंद्रगढ़ के संकुल केंद्र नागपुर अंतर्गत स्थित शासकीय माध्यमिक शाला हर्रा में पहुंचे, जहाँ परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा कक्षों का बारीकी से अवलोकन किया तथा व्यवस्था के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। परीक्षा में बैठे कुल 24 नवसाक्षर शिक्षार्थियों से उन्होंने आत्मीयता पूर्वक संवाद स्थापित किया। उन्होंने सभी नवसाक्षरों को शिक्षा की दिशा में किए जा रहे उनके सराहनीय प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने

बताया कि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सशक्त मार्ग है। श्री गुप्ता ने शिक्षार्थियों को नियमित अध्ययन करने एवं आगे भी शिक्षा की यात्रा निरंतर जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नवभारत साक्षरता अभियान का उद्देश्य समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाना और प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाना है, जिसमें नवसाक्षरों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस निरीक्षण के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री विपिन कुमार पांडे एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रसाद पांडे भी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था का अवलोकन करते हुए नवसाक्षरों को प्रोत्साहित किया और अभियान को सफल बनाने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

क्यूआर कोड से मिली पारदर्शिता की नई राह

बैकुंठपुर। जिले में तकनीक के प्रति ग्रामीण श्रमिकों की बढ़ती रुचि ने पारदर्शिता और सुशासन का एक नया उदाहरण स्थापित किया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार रविवार को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए विशेष रहा क्योंकि मनरेगा श्रमिकों ने स्वयं पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड स्कैन कर सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डिजिटल तकनीक से जुड़े श्रमिकों का यह उत्साह ग्रामीण व्यवस्था में एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाएँ अब पूरी तरह पारदर्शी, सुलभ और साक्ष्य-आधारित हो रही हैं। मनरेगा प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति माह 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। इस दिन श्रमिकों से संवाद, जानकारी साझा करना तथा योजना संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्य की मांग करने, मजदूरी भुगतान की स्थिति जानने, बैंक खाते से संबंधित विवरण प्राप्त करने, जॉब कार्ड आवेदन या संशोधन कराने जैसी सुविधाएँ प्रदान की गईं।

उषा देवी के जीवन में आया स्थिरता और सम्मान का उजियारा

बैकुंठपुर। परिवार जीवन की वह गाड़ी है जिसकी दो मुख्य धुरियाँ पति और पत्नी होते हैं। इनमें से किसी एक का साथ छूट जाने पर दूसरे के कंधों पर संघर्ष दोगुना हो जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों में वर्षों तक पक्के घर का सपना संजोकर रखने वाली श्रीमती उषा देवी अब अपने नए आवास को देखकर भावुक हो उठती हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत तरगंवा में निवास करने वाली उषा देवी के पति मेवालाल का काफी समय पहले निधन हो गया था। खेती से होने वाली सीमित आय में बच्चों की परवरिश और जर्जर कच्चे मकान की देखभाल उनके लिए बेहद कठिन थी। बरसात में छत टपकने के कारण रातभर जागकर बच्चों को भीगने से बचाना उनकी मजबूरी बन चुका था। ऐसी स्थिति में पक्का घर उनके परिवार के लिए बस एक कल्पना मात्र था।

जवानों के त्याग और बलिदान से ही हम सुरक्षित हैं: कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर हुआ आत्मीय संवाद और सम्मान समारोह

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागृह, बैकुण्ठपुर में सादगी और गरिमा से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के अदम्य साहस व अनुकरणीय बलिदान को नमन किया गया।

मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा-हम सभी नागरिक आज सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं तो इसका श्रेय हमारे सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है। उनका त्याग केवल उनका अपना नहीं, बल्कि पूरे परिवार का त्याग होता है। कड़ाके की ठंड हो, बारिश हो या भीषण गर्मी- हमारे जाँबाज सैनिक राष्ट्र की सेवा में हर पल तत्पर रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जवानों का समर्पण न केवल राष्ट्र की रक्षा करता है बल्कि नागरिकों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम में लेफ्टिनेन्ट कर्नल जितेन्द्र कुमार देवांगन (से.नि.), जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, डिप्टी कलेक्टर डी.डी. मंडावी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा क्षेत्र के प्रसिद्ध सैन्य-गाथा कवि जी.पी. नेमा, सुबेदार सुनील कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों का लेपल पिन लगाकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया।

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारी, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों की विधवाओं, सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रितों को ध्वज लगाकर सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाया। सभी अतिथियों ने सैनिकों के अद्वितीय साहस, अनुशासन और बलिदान को सलाम करते हुए उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

स्वास्थ्य मंत्री ने किया रतनपुर में 426.40 करोड़ की अंजनी जलाशय नहर विस्तारीकरण कार्य का भूमिपूजन

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। जनपद पंचायत खड़गवां के रतनपुर में बहुप्रतीक्षित अंजनी जलाशय योजना के नहर विस्तारीकरण एवं सीसी चैनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। लगभग 426.40 करोड़ रुपये की लागत से इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्रीमती श्याम बाई मरकाम, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह करियांम, चिरमिरी नगर पालिक निगम के मेयर राम नरेश राय, रतनपुर के सरपंच नरेंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, जल संसाधन विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार उपस्थित रहे। जल संसाधन विभाग के ए. टोप्पो ने बताया कि अंजनी जलाशय योजना के तहत नहर का निर्माण तो पूर्व में हो चुका था, लेकिन नहर अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप जल आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। अब नहर को पूरी तरह

पक्की (सीसी चैनल) किया जा रहा है, जिससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रतनपुर ग्राम पंचायत की लगभग 75 प्रतिशत भूमि सिंचित होगी, वहीं नए नहर मार्ग से छूटे क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है।

यह परियोजना क्षेत्र का भाग्योदय: स्वास्थ्य मंत्री

मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि छत्तीसगढ़ का हर किसान साल में दो बार खेती कर सके। इसी उद्देश्य के तहत अंजनी जलाशय योजना के नहर विस्तारीकरण के लिए स्वीकृति दी गई है और आज इसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर रतनपुर की अधिकांश भूमि सिंचित होगी तथा शेष 25 प्रतिशत के लिए भी योजनाएँ तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कई कार्य रोक दिए गए थे, जिससे आम जनता प्रभावित हुई। अब भाजपा सरकार में वे सभी रुके हुए कार्य शुरू किए जा रहे हैं जिनकी जनता को वर्षों से आवश्यकता थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि अकेले खड़गवां ब्लॉक में 95 से अधिक सड़क निर्माण कार्य विभिन्न पंचायतों में तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खड़गवां का कोई भी गाँव बिना पक्की सड़क के नहीं रहेगा। जिले को खड़गवां से जोड़ने वाले पुल-पुलियों का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि आज का भूमिपूजन सिर्फ निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के भाग्य बदलने की शुरुआत है। जिस गति से वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, आने वाले समय में विधानसभा का 99 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित भूमि वाला होगा।

बरसात और ठंड की परेशानी से मिली मुक्ति, सुरक्षित शेड ने बढ़ाई दूध उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता

बैकुंठपुर। जिले के बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कसरा के निवासी सियाराम आत्मज धर्मजीत के लिए पहले आय का कोई स्थायी स्त्रोत नहीं था। अकुशल श्रम के सहारे किसी तरह घर का खर्च चल पाता था। परिवार दूध व्यवसाय से आय बढ़ाना चाहता था, परंतु पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उचित स्थान का अभाव सबसे बड़ी बाधा थी। कच्चे स्थान पर बरसात और ठंड के मौसम में पशुओं को संभालना अत्यंत कठिन हो जाता था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत ने महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय उनके लिए व्यक्तिगत पशु शेड निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजना के तहत 1,19,000 की राशि मंजूर की गई तथा निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत कसरा को सौंपी गई। योजना के अनुसार शेड का निर्माण समय पर पूर्ण हुआ। मजबूत, पक्का और सुरक्षित पशु शेड मिलने के बाद श्री सियाराम के लिए पशुपालन का कार्य अत्यंत आसान और व्यवस्थित हो गया। पक्के शेड से उन्हें न केवल पशुओं की सुरक्षा मिली, बल्कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही उन्होंने दो नए दुधारू पशु खरीदे। अब उनके घर में प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री सियाराम कहते हैं पहले कच्चे स्थान में पशु रखना मुश्किल था। बरसात में परेशानी और सर्दी में ठंड से पशुओं की देखभाल करना चुनौती बन जाता था। मनरेगा से मिला यह शेड हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। अब दो और दुधारू भैंस लेकर हम पूरा परिवार दूध उत्पादन को ही मुख्य रोजगार बना चुके हैं। पशुपालन को एक व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में अपनाने से उनकी मासिक आय स्थिर हो गई है।

प्रशिक्षण लेकर आपकी कार्यकुशलता से आवास निर्माण में आएगी तेजी: सीइओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी

मनरेगा अंतर्गत 60 दिन से अधिक अकुशल श्रम करने वाले श्रमिकों का रूरल मेसन प्रशिक्षण शुरू

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। जिले में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य को गति देने तथा राजमिस्त्रियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से रूरल मेसन ट्रेनिंग का नया सत्र आज से आरंभ हुआ। राज्य शासन के निर्देशानुसार शुरू हुए इस प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने आरसेटी पहुँचकर किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह अवसर न केवल श्रमिकों के कौशल को विकसित करेगा, बल्कि गांवों में आवास निर्माण की गति को भी बढ़ाएगा।

मनरेगा के तहत अब श्रमिकों को केवल अकुशल श्रम तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत चयनित 35 श्रमिकों को एक माह का निःशुल्क राजमिस्त्री प्रशिक्षण आरसेटी में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए सोनहत जनपद पंचायत के तीन ग्राम पंचायतों मधौरा से 16, लटमा से 15 एवं कटगोड़ी से 4 मनरेगा पंजीकृत अकुशल श्रमिक युवाओं का चयन किया गया है प्रशिक्षण पूरा होने पर ये युवा प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य निर्माण कार्यों में दक्षता के साथ योगदान दे सकेंगे। प्रशिक्षण सत्र के आरंभ में डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों की मेहनत और अनुभव को अब कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे अकुशल श्रम से आगे बढ़ते हुए अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से अपील की कि वे पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे चलकर अपने तथा आसपास के ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ सहयोग दें।

विधानसभा सत्र दौरान अवकाश पर प्रतिबंध

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का सप्तम सत्र 14 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2025 तक आहूत किया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा आज दिनांक से 24 दिसम्बर 2025 तक विधानसभा सत्र के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्र अवधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय/मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यक कार्य/अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख एवं जिला स्तर के अधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।

करोड़ों खर्च कर बना पर्यटन स्थल हुआ बदहाल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कभी अपनी मनमोहक सुंदरता और बोटिंग के कारण दूर-दूर से आने वाले पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना रहा पर्यटन स्थल आज बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से विकसित यह ड्रीम प्रोजेक्ट आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा खर्च होने के बाद भी यह क्षेत्र कब फिर से गुलजार होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नए वर्ष में तो हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि जहां कभी भीड़ उमड़ती थी, वहां अब उंगलियों पर गिनने लायक लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल यहां पर विजिट के नाम पर खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ली जा रही है लेकिन इस योजना के उद्देश्य का उचित लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 किनारे ग्राम पंचायत जयनगर व तेलईकछार के मध्य एसईसीएल की लीज भूमि पर स्थित अनुपयोगी क्वारी नंबर 6 में वर्षों पूर्व करोड़ों रुपए खर्च करने

उपरांत एसईसीएल प्रबंधन व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था। करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किए गए पर्यटन स्थल के शुरुआती दिनों में यहां बोटिंग, झूलों, फव्वारों, विश्राम स्थलों, फोटो पॉइंट्स की वजह से पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि इन खूबसूरत यादों की जगह उजड़ी हुई झोपड़ियां, टूटे रास्ते और वीरानी ने ले ली है। यहां पर उचित मॉनिटरिंग के अभाव में आज स्थिति यह है

कभी पीएम मोदी के ट्वीट से चमका था सितारा, आज वीरान

कि दूर दराज क्षेत्रों से यहां आने वाले पर्यटकों को उचित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उनमें निराशा देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यूं तो यहां की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर विजिट किया जाता है लेकिन अधिकारी केवल यहां बोटिंग का लुत्फ उठाकर केवल प्लानिंग तैयार करके चले जाते हैं। वास्तव में यहां के विकास की ओर अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ठोस कदम उठाते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आलम यह है कि अब पर्यटन स्थल में ना तो पर्यटकों को ठहरने की कोई उचित व्यवस्था है और ना ही मनोरंजन के उचित साधन उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटकों को केवल बोटिंग का ही लुत्फ मिल पा रहा है। यहां पर हजारों रुपए खर्च करके तैयार किए गए बांस की झोपड़ी भी पहली आंधी में ही गिरकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिनका आज तक मरम्मत नहीं कराया जा सका है। पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने कई कार्यों को पूर्व में ठेका हुआ और ठेका स्थगित हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सका है। पूर्व में अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया था कि स्थानीय लोगों के अलावे अन्य जिलों से भी ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में शामिल करके अच्छे ठेकेदार के जिम्मे इस कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी दी जाए, जिससे पर्यटन स्थल के सौंदर्यता पर ग्रहण न लग सके। बावजूद इसके यहां की सुध शासन प्रशासन द्वारा न लेने की वजह से करोड़ों की इस मनमोहक स्थल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाती नजर आ रही है। पर्यटन स्थल के शुरुआती दिनों में दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक यहां आकर भरपूर मनोरंजन कर लुत्फ उठाते थे लेकिन अब यहां की स्थिति बदहाल होने से पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। इस पर्यटन स्थल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर किया जा चुका है और कोल इंडिया द्वारा भी इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा चुका है। बावजूद इसके वर्तमान स्थिति में पर्यटन स्थल काफी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है।

सी मार्ट भी हुआ खंडहर

जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन स्थल के समीप लाखों रुपए की लागत से सी मार्ट का निर्माण कार्य कराया गया था। उचित देखरेख के अभाव में अब सी मार्ट भी खंडहर हो चुकी है। सी मार्ट का कोई उपयोग नहीं होने की वजह से शासन की लाखों रुपए का दुरुपयोग करके नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है।

बताया जा रहा है कि पूर्व में सी मार्ट को रेस्टोरेंट के रूप में विकसित किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वह भी केवल कोरमपूर्ति ही साबित हो चुकी है।

लेबर कोड लागू होने के बाद कोल कंपनियों के त्रि-आयामी कमेटियों पर खड़े हुए सवाल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। लेबर कोड लागू होने की औपचारिक घोषणा के साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड एसईसीएल और इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों में सक्रिय त्रि-स्तरीय कमेटियों के भविष्य को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। कई वर्षों से चल रही ये समितियां जिनमें कर्मचारी प्रतिनिधि, यूनियन प्रतिनिधि और प्रबंधन के अधिकारी शामिल होते हैं। कर्मचारियों के हित, सुरक्षा, कल्याण, मानकीकरण, वेतन-भत्तों और अनुशासनात्मक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बनी हुई थीं। लेकिन नए लेबर कोड के लागू होने के बाद इन कमेटियों की संरचना, अधिकार और यहां तक की अस्तित्व को लेकर भी अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोल इंडिया और उससे जुड़े विभिन्न स्तरों पर दर्जनों समितियां वर्षों से सक्रिय हैं। कोल इंडिया एपेक्स जेसीसी, कोल इंडिया बोर्ड, मानकीकरण समिति, सीपीआरएमएस-एनई की बायोटी टीम, हाई पावर कमेटी, ठेका श्रमिकों के लिए संयुक्त समिति, सीआईएल रिलिफ ट्रस्ट, जेबीसीसीएआई और सीएमपीएफ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी संचालित हैं।इसी तरह कंपनी स्तर, एरिया स्तर और यूनिट स्तर पर भी समानांतर समितियां चलती हैं, जिनकी सहभागिता कर्मचारी व्यवस्थापन की रीढ़ मानी जाती रही है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए लेबर कोड जिसमें वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, औद्योगिक संबंध कोड और ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड शामिल हैं, कई प्रक्रियाओं को नई परिभाषाएं देते हैं। हालांकि 2020 के संबंधित केंद्रीय नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं, इसी कारण कंपनियां और कर्मचारी दोनों असमंजस में हैं कि पुरानी समितियां यथावत रहेंगी या फिर पूरी संरचना को नए प्रारूप में ढालना होगा। खास बात यह है कि कोल सेक्टर में संयुक्त सहभागिता की परंपरा दशकों से चली आ रही है। कर्मचारी कल्याण योजनाएं, खान सुरक्षा मानक, ठेका श्रमिकों से जुड़े विवाद, पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित निर्णय सब कुछ इन समितियों के माध्यम से ही गति पकड़ता रहा है। नए कोड के चलते यदि इन समितियों की संरचना बदली या सीमित हुई, तो इसका सीधा असर कर्मचारी-प्रबंधन संवाद पर पड़ेगा। यही वजह है कि यूनियनें भी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रही हैं। कोल इंडिया व एसईसीएल के सूत्रों की मानें तो केंद्रीय नियम जारी होने के बाद ही यह निर्धारित हो सकेगा कि मौजूदा समितियों का कायदा-कानून कैसे बदलेगा। कई समितियों को नए कोड के अनुरूप पुनर्गठित किया जा सकता है, कुछ को विलय और कुछ को समाप्त भी किया जा सकता है।

फिलहाल कोल सेक्टर में कर्मचारी समुदाय से लेकर उच्च प्रबंधन तक में यही चर्चा तेज है कि लेबर कोड को लागू करने से कोल कंपनियों की दशकों पुरानी संयुक्त प्रबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव आने वाला है।

रेवतपुर एवं धनवार जंगल में 362 बोरी अवैध धान जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन पर की जा रही सतत निगरानी के तहत दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के नेतृत्व में राजस्व अमले ने अंबिकापुर से धंधापुर समिति जा रहे लगभग 300 बोरी अवैध धान से भरी आयशर गाड़ी को पीछा कर ग्रामीण क्षेत्र रेवतपुर में पकड़ा। प्रशासनिक दल द्वारा वाहन को तत्काल जब्त कर थाना राजपुर के सुपुर्द किया गया।

इसी क्रम में वाड्रफनगर अनुभाग अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम धनवार के जंगल क्षेत्र में अवैध धान परिवहन कर रहे एक पिकअप वाहन को 7 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा। जांच के दौरान वाहन में 62 बोरी अवैध धान पाया गया। पिकअप को जब्त कर थाना वाड्रफनगर के सुपुर्द किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य खरीदी को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि जिसमे अवैध धान परिवहन, संग्रहण एवं अवैध रूप से खपाने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने किसानों एवं नागरिकों से भी अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है, ताकि खरीदी व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित रहे।

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर में मना समरसता दिवस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। भारत रत्न और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बिश्रामपुर द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय में समरसता दिवस गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया।

कार्यक्रम की मुख्य आकर्षक गतिविधि रंगोली प्रतियोगिता रही। छात्र-छात्राओं ने संविधान, सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, राष्ट्रनिर्माण और अंबेडकर के प्रेरक संदेशों को रंगों में सजाकर अद्भुत कलाकृतियां पेश की। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि युवा पीढ़ी इस तरह की प्रतियोगिताओं से न केवल

अपनी कला दिखाती है बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी जीवंत बनाती है। रंगोली प्रतियोगिता के बाद अभाविप की ओर से विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।अभाविप बिश्रामपुर के नगर मंत्री रितेश यादव ने कहा कि 6 दिसंबर 1956 को पंचतत्व में विलीन हुए बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता ही नहीं, बल्कि दलित, शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग के अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक भेदभाव मिटाने, शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। समरसता दिवस हमें याद दिलाता है कि समानता और न्याय के बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है।

करंजी रेलवे साइडिंग को लेकर डिप्टी सीएम को दिया ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। करंजी रेलवे साइडिंग से उठ रहे कोल डस्ट अब ग्रामीणों के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। गांव से मात्र 150ङ्क200 मीटर की दूरी पर संचालित इस साइडिंग में प्रतिदिन ट्रक, ट्राला और हाइवा से कोयले का भारी परिवहन होता है। इसके बाद यहां कोयले की लोडिंगङ्कअनलोडिंग का काम होता है, जिसके दौरान उठने वाला काला गुब्बार पूरे करंजी ग्राम पर मौत का साया बनकर छा रहा है। सप्ताह भर से ग्रामीणों द्वारा कोल परिवहन कार्य बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुरजपुर जिला मुख्यालय में प्रवास पर सोमवार को आए डिप्टी सीएम अरुण साव को ज्ञापन देकर कोल परिवहन को बंद कराए जाने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव को दिए ज्ञापन में ग्राम पंचायत करंजी की सरपंच कुसुम कुंवर और उपसरपंच उर्मिला यादव ने उल्लेख किया है कि करंजी साइडिंग बंद कर अन्यत्र स्थानांतरित की जाए। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गांववासियों का धैर्य जवाब दे रहा है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोल साइडिंग संचालन में धूल रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। न यहां नियमित पानी का छिड़काव हो रहा है, न ही डस्ट कंट्रोल सिस्टम है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बच्चों और बुजुर्गों में खांसी, सांस फूलना, दमा जैसी परेशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। ग्राम के आसपास लगभग 100 हेक्टेयर खेती कोल डस्ट से लगातार बर्बाद हो रही है। फसलों की पत्तियां काली पड़ रही हैं और उपज में भारी गिरावट हो चुकी है। कोल डस्ट में मौजूद सिलिका के कारण सिलिकोसिस और कोयले की महीन धूल से न्यूमोकोनियोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बना हुआ है। यदि कोयले में एस्बेस्टॉस की मिलावट पाई गई तो इससे एस्बेस्टॉस पॉइजनिंग जैसी लाइलाज बीमारी का खतरा भी हो सकता है। सरपंच ने आवेदन में उल्लेख किया है कि माइंस एक्ट 1952, माइन रूल्स 1955 और कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में ऐसे प्रदूषण को रोकने के स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन करंजी साइडिंग में इनका पालन तक नहीं हो रहा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक स्वस्थ व गरिमामय जीवन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यहां ग्रामीण इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। चौंकाने वाला आरोप यह भी लगाया गया है कि साइडिंग में कोयले के साथ एश व चारकोल डस्ट मिक्स कर उसे कोयले की दर पर बेचा जा रहा है। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान, कंपनियों की छवि धूमिल और परिवहन में भारी अनियमितता जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर सूरजपुर, पर्यावरण अधिकारी अंबिकापुर और खनिज अधिकारी सूरजपुर को पहले ही आवेदन दिया था। पर्यावरण अधिकारी की जांच में साइडिंग संचालक के पास कोई भी वैध अनुमति-पत्र या दस्तावेज नहीं मिला, जिसकी पंचनामा प्रति ग्रामीणों ने आवेदन में संलग्न की है। बावजूद इसके साइडिंग संचालन जारी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। दावा यह भी किया गया है कि करंजी इसके टोला-मजरों और आसपास के 810 लोग लगातार कोल प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। सरपंच और उपसरपंच ने उप मुख्यमंत्री से मांग किया है कि करंजी रेलवे साइडिंग को तत्काल बंद कर, किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए और जब तक यह न हो, तब तक सभी प्रदूषण नियंत्रण मानकों को सख्ती से लागू कराया जाए।

तातापानी महोत्सव हेतु तैयारियां शुरू, कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ ने लिया जायजा

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तातापानी में आगामी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव की तैयारी को लेकर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने तातापानी पहुंचकर पूरे मंदिर तथा मेला परिसर का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग, परिवहन व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति तथा गर्म पानी के कुंडो की सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में सौंदर्यीकरण, रंग-रोगन और हेलीपेड स्थल, प्रवेश एवं निकास मार्गों की व्यवस्थित योजना के लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया। तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने मंदिर परिसर में साफ-सफाई और रंग-रोगन के कार्य को शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेला स्थल का निरीक्षण कर समतलीकरण, टेंट व्यवस्था, मंच, विभागीय स्टॉल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को समय से तैयार करने की बात कही। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि विभागवार दायित्वों के अनुसार सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करे।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तातापानी में विशाल मेले का आयोजन होता है। धार्मिक आस्था, और गर्म जल स्रोत के कारण तातापानी में जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी तातापानी महोत्सव सुव्यवस्थित रूप में आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का बेहतर निर्वहन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने धनवार व चुना पाथर चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने आज अलसुबह विकासखण्ड वाड्रफनगर से लगे अंतरराज्यीय चेक पोस्ट धनवार का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री कटारा ने चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों से जांच प्रक्रिया तथा सुरक्षा की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की

जाएगी। उन्होंने अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच प्रक्रिया, सीसीटीवी, वाहनों के प्रवेश-निकास पंजी तथा कर्मचारियों की ड्यूटी सूची का भी अवलोकन किया। उन्होंने चेक पोस्ट में संबंधितों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे हर स्थिति में सतर्क रहें और आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का गंभीरता से पालन करने और ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने को कहा। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि यदि किसी वाहन में धान या अन्य कृषि उपज परिवहन का संदेह हो, तो उसकी पूरी जांच करे। उन्होंने संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच कार्यवाही पारदर्शी, त्वरित और निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। इस दौरान कलेक्टर ने चुना पाथर चेक पोस्ट का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए।

पारदर्शी और सुगम धान खरीदी व्यवस्था से किसान मनु तिर्की हुए प्रभावित

धान का मिल रहा सर्वाधिक दाम, बच्चों की शिक्षा और घर की आर्थिक स्थिति में आया सुधार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत जिले के धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मानिक प्रकाशपुर के किसान मनु तिर्की ने धान खरीदी की प्रक्रिया को आसान, सुगम और भरोसेमंद बताते हुए अपना अनुभव साझा किया। किसान तिर्की ने बताया कि उनके पास कुल 161 क्विंटल धान का रकबा है। इस खरीफ सीजन में उन्होंने खैरबार धान उपार्जन केंद्र से 60 क्विंटल का पहला टोकन कटाया, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। समिति केंद्र में टोकन कटाने से लेकर धान तौल तक की पूरी प्रक्रिया सहज, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रही। उन्होंने बताया कि उपार्जन केन्द्र पहुंचते ही सबसे पहले नमी परीक्षण किया गया और उसके बाद तत्काल बारदाना उपलब्ध कराया गया। समिति के कर्मचारियों के सहयोग से धान विक्रय करने में कोई विलंब नहीं हो रही है। धान की तौल पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है, जिससे किसानों में विश्वास और उत्साह बढ़ा है। मनु तिर्की ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की किसान हितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी हो रही है और 3100 रुपये प्रति क्विंटल का सर्वाधिक दाम से मिलने से किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि धान का सर्वाधिक दाम मिलने से खेती का विस्तार करने में मदद मिल रही है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद हो रही है। किसान मनु तिर्की ने धान खरीदी व्यवस्था पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिला प्रशासन द्वारा सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि प्रत्येक किसानों को धान विक्रय के दौरान सुगम और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े।

छत्तीसगढ़ मानस संगठन जिला सूरजपुर की प्रथम बैठक संपन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। छत्तीसगढ़ मानस संगठन जिला सूरजपुर का प्रथम बैठक का आयोजन गायत्री मंदिर, भैयाथान में किया गया। बैठक में जिले व तहसील स्तर के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन और सामूहिक वंदना से की गई। इसके बाद संगठन के उद्देश्यों एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना है। इसी क्रम में तीन प्रमुख संकल्प लिए गए जिसमे पहला विद्यार्थियों में संस्कारात्मक शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देना, दूसरा जिन गांवों में रामायण मंडली सक्रिय नहीं है, वहाँ नई टीम बनाकर सांस्कृतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना, तीसरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सामाजिक आयोजनों के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना शामिल है। बैठक में जिला व तहसील स्तरीय पदाधिकारियों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा स्थानीय कार्यकताओं ने अपने विचार साझा किए और संगठन को मजबूत बनाने हेतु सुझाव भी रखे। अंत में सभी पदाधिकारियों ने एकमत होकर संकल्प लिया कि आगामी दिनों में गांव-गांव पहुंचकर सांस्कृतिक जागरण और समाज सेवा के कार्यों को गति दी जाएगी। संगठन की पहली जिला स्तरीय बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

आरएसएस का गृह संपर्क अभियान, शताब्दी वर्ष पर घर-घर पहुँचा राष्ट्र निर्माण का संदेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पूरे देश में गृह संपर्क अभियान चला रहा है। इसी अंतर्गत खंड रामानुजनगर में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा घर-घर जाकर लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वयंसेवक प्रत्येक परिवार से मिलकर भारत माता का चित्र, संघ का साहित्य, पत्रिकाएँ एवं सूचनापत्र भेंट कर रहे हैं, साथ ही समाज को संगठित करने वाली महत्वपूर्ण बातों पर संवाद भी कर रहे हैं। इनमें राष्ट्रप्रेम, सामाजिक समरसता, एकता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, तथा कुटुंब प्रबोधन जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल हैं। खंड कार्यवाह संत साहू ने बताया कि शताब्दी वर्ष में गृह संपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य संघ की विचारधारा एवं राष्ट्रहित के भाव को घर-घर तक पहुँचानाह्व है। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और जागरूकता ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। अभियान में ब्रिजेश राजवाड़े, यादवेन्द्र दुबे, प्रशांत उपाध्याय, शिवम्दुबे, पीयूष साहू, अभिषेक साहू, पंकज शुक्ला, लालकेश्वर सिंह, बादल, अर्चित, आराध्य, हर्ष साहू सहित अनेक स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक घर-घर जाकर संपर्क स्थापित किया और लोगों के बीच संगठन एवं राष्ट्रहित के संदेश को फैलाया। यह अभियान रामानुजनगर क्षेत्र में सकारात्मक जनजागरूकता का माध्यम बन रहा है और समाज में संगठन, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

मिशन समन्वयक ने ली विकासखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। जनपद सभा कक्ष भैयाथान में जिला मिशन समन्वयक (समग्र शिक्षा) मनोज कुमार साहू के निर्देशन में शिक्षा विभाग की विकासखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान में संचालित प्रमुख योजनाओं,.सामाजिक अंकेक्षण, बोर्ड परीक्षा तैयारी, मध्यान्ह भोजन संचालन, विज्ञान विषय का 5 दिवसीय प्रशिक्षण, एपीएआर, डी-ग्रेड स्कूलों का निरीक्षण, एफएलएन कार्यक्रम सहित अन्य गतिविधियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिला मिशन समन्वयक ने सभी संकुलों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी फुलसाय माराबी, खण्ड स्त्रोत समन्वयक सुरेन्द्र दुबे, एपीसी सुरविंद गुर्जर तथा सभी संकुल समन्वयक उपस्थित रहे। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, समयबद्ध कार्ययोजना और विद्यालयों में नियमित निरीक्षण पर विशेष जोर दिया गया।

अमेरा ओपन कास्ट माइंस हिंसक आंदोलन कौन जिम्मेदार ?

मनोज कुमार सिंह

अम्बिकापुर। अमेरा ओपन कास्ट माइंस को लेकर जो खूनी संघर्ष हुआ सरगुजा के परिप्रेक्ष्य मे ऐसा हिंसक आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। यह आंदोलन लौह रक्त नियम पर संगठित था। अमेरा में इस संघर्ष का बीजारोपण 2010 के दशक में ही हो चुका था। जब एसईसीएल के भ्रष्ट अधिकारियों, सर्वेयरों और पटवारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। भूमि अधिग्रहण मे राजस्व दस्तावेजों में पटवारियों द्वारा और मुआवजे व नौकरी के लिए तात्कालिन कोल अधिकारियों व मैदानी कर्मचारियों द्वारा वृहद हेरफेर कर लाभार्जन किया गया। यह हिंसक आंदोलन उक्त पौधे की नर्सरी है। भूमि अधिग्रहण के समय आज से बीस वर्ष पूर्व हितग्राहियों को कालरी में नौकरी नहीं दी गई और आज उन्हे इसलिए नौकरी नहीं दी जा रही है कि अमेरा हितग्राहियों की आयु सीमा अधिक हो गई है। ऐसे मे वे उत्पादन की दृष्टि सेएसईसीएल के लिए लाभप्रद नही रहे। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि ऐसे मे उन हितग्राहियों को भूमि अधिग्रहण तिथि से वर्तमान तक सेवा अवधि के दौरान एक कालरी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले समस्त आर्थिक स्वत्वो का अबिलंब भुगतान कर दिया जाना चाहिए। हिंसक अमेरा आंदोलन ने सरगुजा के माथे पर कुछ पूरक प्रश्न छोड़ गये है। जैसे क्या इस संघर्ष ने परसा केते आंदोलन और कमलेश्वरपुर की घटना को कोई मार्ग दिखा दिया है ?

जिस विधानसभा क्षेत्र ने एक पूर्व उपमुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री दिया है, वहां अमेरा जैसी घटना का होना राजनैतिक निष्क्रियता,व जन सरोकार से उदासीनता की चरम राजनीतिक स्थिति है। अमेरा ओपन कास्ट माइंस और उसके आसपास स्थित गांववालो द्वारा कोयला चोरी करना, इनके मध्य तनाव का एक स्थायी कारण है। संभव है कि यही स्थायी तनाव हिंसा की चिंगारी बनी।

कलेक्टर के आदेश की अधिकारी कर्मचारी कर रहे नारफरमानी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु रकबा कटौती व पंजीयन में हुई गड़बड़ियों को सुधारने दिए गए कलेक्टर के फरमान की यहां रामानुजनगर के अधिकारी कर्मचारी नारफरमानी कर रहे हैं। कलेक्टर के मातहत अधिकारियों द्वारा आदेश की नाफरमानी से एक बार पुनः किसानों के मन में निराशा के साथ आक्रोश का भाव उत्पन्न हो गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एस जयवर्धन द्वारा एक आदेश जारी कर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी व पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया था कि अधिकारी कर्मचारी संबंधित सोसायटी क्षेत्रों में कैम्प लगाकर किसानों की धान बिक्री में आ रही समस्याओं का 9 दिसंबर तक समाधान कर कलेक्टर को सूचित करें। मगर एक भी समिति में जिनकी ड्युटी लगाई गई थी वे अधिकारी कर्मचारी समस्याओं का निराकरण करने नहीं पहुंचे। जबकि भू अभिलेख कार्यालय रायपुर के निदेर्शानुसार कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के अधिकारी कर्मचारी किस तरह बेलगाम हो गए हैं। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार लचर हो गई है कलेक्टर को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। बता दें कि यहां रामानुजनगर तहसील में करीब 12 हजार 8 सौ ऐसे आवेदन पत्र तहसीलदार के यहां पड़े हुए हैं जिनका रकबा कटौती, कैरी फॉरवर्ड, एग्री स्टैक पंजीयन तथा नवीन पंजीयन किया जाना है, यदि किसानों का रकबा सुधार नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर किसान अपनी उपज नहीं बेंच पाएंगे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का प्रसारण होते ही प्रभावित किसानों की भीड़ अपना अपना दस्तावेज लेकर सोसायटियों में पहुंची थी लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारीयों के उपस्थित नहीं होने से उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा।

डबरी निर्माण से सूरत कुमारी की बदली किस्मत, बढ़ी आमदनी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से किसानों के खेतों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिलने से किसानों को खेती-बाड़ी में आसानी हो रही है तथा उनके आजीविका के अवसर में भी वृद्धि हुई है। जिले के अम्बिकापुर विकासखण्ड के ग्राम कुम्हरता की सूरत कुमारी ने मनरेगा अंतर्गत अपने खेत में डबरी का निर्माण करवाया है। उन्हें जैसे ही मनरेगा अंतर्गत डबरी निर्माण हेतु मिलने वाली सहायता की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत योजना का लाभ लेने की ठानी। उन्होंने रोजगार सहायक से संपर्क किया और डबरी निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया। उन्हें वर्ष 2024-25 में 2.99 लाख रूपए की डबरी स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने 30 *30 की साईज की डबरी का निर्माण कराया, वर्तमान में इसमें 06 फीट पानी भरा हुआ है। सूरत बताती हैं कि उनके पास 3.00 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसमें वे बारिश के दिनों में धान की ही खेती कर पाते थे। सिंचाई के लिए और दूसरा कोई साधन ना होने के कारण गर्मी और सर्दी के मौसम में खेत सूने रहते थे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें डबरी निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे उन्होंने मनरेगा से प्राप्त किया। डबरी निर्माण से सिंचाई के लिए केवल वर्षा जल पर निर्भर रहने वाली सूरत कुमारी के खेतों में अब बारहों माह अलग-अलग तरह की फसल लहलहाती है। वर्तमान में वे बहुफसलीय खेती का लाभ ले रहे हैं, उन्होंने अब साग-सब्जी, गेंहू, अरहर सहित अन्य फसल भी लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही डबरी निर्माण से 1231 मानव दिवस रोजगार भी सृजित हुआ जिससे गाँव के कई लोगों को काम मिला। सूरत कुमारी के आजीविका का स्त्रोत अब खेती बाड़ी ही नही रहा, उन्होंने डबरी में मछलीपालन करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि मछलीपालन से उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। उन्होंने बताया कि डबरी में इस बार 5 किलो मछली के बीज डाले हैं, जिनकी वर्तमान ग्रोथ अच्छी हो रही है। सूरत का परिवार अब बहुत खुश है, डबरी निर्माण से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। उनके कृषि कार्य हेतु पानी का समस्या का समाधान हो गया है। सूरत ने योजना की प्रशंसा करते हुए, इस हेतु शासन का आभार व्यक्त किया। सूरत अब स्वयं गांव वालों को भी योजना का लाभ लेने प्रेरित कर रहीं है।

रौनियार समाज के तीसरी बार अध्यक्ष बने जितेन्द्र गुप्ता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पत्थलगांव। रौनियार समाज बैठक में जितेन्द्र गुप्ता को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छोटेलाल गुप्ता, प्रमोद गुप्ता को कोषाध्यक्ष, कुंदन गुप्ता को सचिव, मीडिया प्रभारी मनोहर गुप्ता और सह सचिव रोहित गुप्ता को बनाया गया। रौनियार समाज की नई कार्यकारिणी जनवरी 2026 से प्रभावशील होगा। जनवरी के प्रथम बैठक में नए पदाधिकारीयो को शपथ दिलाया जाएगा। जितेन्द्र गुप्ता ने अध्यक्ष बनने पर रौनियार समाज के सभी सदस्यों का आभार जताया। जितेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आप सभी के द्वारा एक बार फिर से मुझे अध्यक्ष चुना है। आप सभी के द्वारा दिये गए जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिस करूंगा। समाज हित मे समाज के लिए काम करता रहूंगा। आप सभी ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। उसे पूरा करने की लगातार कोशिश करुंगा। छोटेलाल गुप्ता ने उपाध्यक्ष बनने पर समाज से कहा कि आप सभी ने मुझे पहली बार बड़ी जिम्मेदारी दि है उसे पुरी तरह निभाने का प्रयास करूंगा। प्रमोद गुप्ता ने कोषाध्यक्ष बनने पर कहा रौनियार समाज ने फिर से मुझपर विश्वास जताते हुए मुझे कोषाध्यक्ष बनाया है आप सभी से मिले जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने कोशिस करूंगा। कुन्दन गुप्ता ने सचिव बनने पर समाज का आभार मानते हुए कहा कि रौनियार समाज ने मुझे लगातार चौथी बार सचिव बनाया है। आप सभी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपके द्वारा दिये जिम्मेदारी को अवश्य पूरा करने सतत प्रयास करता रहूंगा। मेरी हमेशा कोशिश रही है की रौनियार समाज पत्थलगांव का नाम बना रहे। पत्थलगांव रौनियार समाज के मुखिया अरुण गुप्ता ने सभी नवनियुक्त रौनियार समाज के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी समाज के हित मे काम करे समाज का नाम आगे बढाने में अपना योगदान दे।

सड़क निर्माण में लापरवाही पर भाजपा के लोगों ने ही जेसीबी से उखड़वाई सड़क

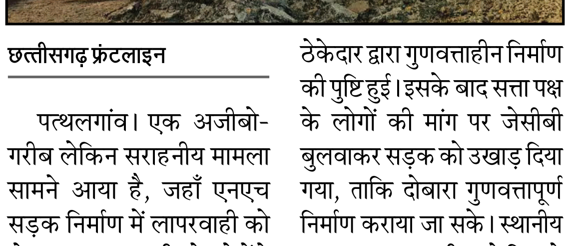

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पत्थलगांव। एक अजीबो-गरीब लेकिन सराहनीय मामला सामने आया है, जहाँ एनएच सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर भाजपा सत्ताशीन के लोगों ने ही खुलकर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि जनता का पैसा और प्रदेश सरकार की राशि का बंदरबांट किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध बढ़ने पर एनएच विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचे और स्थल का निरीक्षण किया। जांच में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण की पुष्टि हुई। इसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों की मांग पर जेसीबी बुलवाकर सड़क को उखाड़ दिया गया, ताकि दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जा सके। स्थानीय जनता इस कदम की खुले दिल से सराहना कर रही है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए भी गलत कार्य के खिलाफ खड़े होना कम ही देखने को मिलता है। वहीं, इस पूरे मामले पर विपक्ष की चुप्पी पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। संदेश स्पष्ट है सुशासन में समझौता नहीं सड़क हो या सिस्टम, कोताही अब नहीं चलेगी।

रा.से.यो. एवं यूनिसेफ ने कौशलपुर में चलाया ग्राम संपर्क अभियान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। यूनिसेफ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित पारा-सुरक्षित लइकामन 3.0ह्व अंतर्गत ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर में व्यापक ग्राम संपर्क एवं जनजागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामानुजनगर के रा.से.यो. इकाई के स्वयंसेवकों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों एवं ग्रामीणों को दैनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। इनमें हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, गुड टच-बैड टच, संतुलित आहार, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसा, भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल थे। ग्रामीणों तक प्रभावी संदेश पहुँचाने के लिए नुक्कड़ नाटक, परिचर्चा, स्लोगन एवं शपथ जैसे माध्यमों का उपयोग किया गया। प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा ग्राम के आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में सहभागिता की और इसे सकारात्मक रूप से सराहा। अभियान में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एवं यूनिसेफ का सहयोग और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। कार्यक्रम में रा.से.यो. इकाई से 12 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, वहीं कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार शर्मा ने सम्पूर्ण आयोजन का नेतृत्व करते हुए जागरूकता गतिविधियों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया। ग्राम कौशलपुर में आयोजित यह कार्यक्रम बच्चों एवं समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। ग्रामीणों ने आशा व्यक्त की कि ऐसे जागरूकता अभियानों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

सम्पादकीय

धर्म स्थलों की पवित्रता

पंजाब ने अपने तीन शहरों की पवित्रता में धार्मिक पर्यटन की एक और छलांग लगा दी। अमृतसर, दमदमा साहिब तलवंडी साबो और केसगढ़ साहिब अब इस हद तक पवित्र होंगे कि न वहां शराब और न ही मांस बिकेगा। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का खाका इस तरह बन रहा कि बसें भी मुफ्त में घुमाएंगी। धार्मिक पर्यटन की परिधि को सशक्त करते हुए पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र को इसकी पवित्रता और विशेषता से जोड़ा है। यानी कि सिख पर्यटन की दृष्टि से पंजाब के महत्त्वपूर्ण शहर अपना आचरण व व्यवहार बदलेंगे। इसी संदर्भ में हिमाचल को भी धार्मिक स्थलों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार करना होगा। खास तौर पर आनंदपुर साहिब के बदलावों के साथ नयना देवी सर्किट को जोड़ते हुए एक उदाहरण पेश करना होगा। धार्मिक स्थलों की अधोसंरचना, क्षमता व सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ, इन्हें पवित्र नगरियों की परिभाषा में सुव्यवस्थित करना होगा। ये स्थल महज मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक मान्यताओं को प्रदर्शित करने की अनुशासित पद्धति का नेतृत्व करें। कांगड़ा, चिंतपूर्णी, चामुंडा, ज्वालाजी, नयनादेवी, दियोटसिद्ध और बालाजी सुंदरी परिसरों के साथ जुड़े कस्बों व शहरों में तत्काल प्रभाव से पवित्र स्थलों का दर्जा देते हुए वहां शराब और मांस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसके लिए नीति, नियम, पद्धति और गवर्निंग बाड़ी चाहिए। हिमाचल में धार्मिक स्थल विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करके ही हम इन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिला सकते हैं।

हर साल कुछ मंदिरों में अप्रवासी भारतीय आकर विशेष आभूषण या मां के श्रृंगार में सोना-चांदी अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के विभिन्न भागों से हिमाचल के कुछ मंदिरों के लिए विशेष आस्था प्रस्तुत की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में तीर्थ यात्राओं, समागमों और नवरात्रि महोत्सवों का आयोजन होता है। ऐसे में अगर धार्मिक स्थलों को धार्मिक नगरों के परिवेश में विकसित करते हुए इन्हें श्रद्धा के पैमानों में पवित्र घोषित किया जाए, तो आर्थिकी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अभी हिमाचल के मंदिर स्थल बाकी शहरों की तरह ही अपने औचित्य के लिए संघर्ष कर रहे । इससे शहर और मंदिर व्यवस्था के बीच न तो सामंजस्य और न ही एकरूपता का श्रृंगार हो रहा है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की व्यवस्था के बाद पंजाब के धार्मिक स्थलों में आ रहे परिवर्तनों से सीखना होगा। बात अब मंदिरों के प्रबंधन से आगे धार्मिक नगरों के प्रबंधन की है। इन शहरों के विकास का एक खाका बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि धार्मिक पवित्रता के मानदंड हर सूरत लागू हों। दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का स्तर, स्टेट ऑफ आर्ट अधोसंरचना से मुकम्मल किया जाए। चिंतपूर्णी में दर्शन योजना शुरू हुई, तो भक्तों ने आय बढ़ा दी। इसी तरह हर मंदिर के दर्शन और पूजा पद्धति का स्तर शखेकाच्चारण से पुष्ट करना होगा। धार्मिक नगरी विकास बोर्ड या प्राधिकरण को हर मंदिर स्थल के लिए एक विकास योजना बनानी होगी ताकि परिक्रमा और पर्वतीय परिवेश में स्थित हमारे धार्मिक स्थल हर आने वाले के लिए सुकून और पवित्रता का एक पैकेज बन जाएं। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल के ऊना, पांवटा साहिब और मणिकरण के विकास को सिख पर्यटन के साथ नत्थी करके विविधता लाई जा सकती है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिवसीय भारत दौरा नई दिल्ली और मॉस्को में दोस्ती की एक नई इबारत लिख गया है। दोनों देशों ने मजबूत आर्थिक साझेदारी के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने और व्यापार घाटे पर भारत की चिंताओं को दूर करने पर सहमति जताई। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत के लिए अमेरिका के मुकाबले रूस ज्यादा भरोसेमंद है। शिखर बैठक ने इस भरोसे को और मजबूती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पश्चिम के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। हमारी विदेश नीति के केंद्र में उसके राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास प्राथमिकता में हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यूक्रेन में युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। इन सबके बीच पुतिन की भारत यात्रा एक बड़े वैश्विक बदलाव की ओर इशारा करती है। भारत अगर अमेरिका की तनी हुई भौंहों की उपेक्षा करने में सफल रहा तो रूस भी पश्चिमी देशों को ठेंगे पर लेने और भारत में अपना बाजार बढ़ाने के प्रयासों में सफल रहा। पुतिन की इस यात्रा के बाद यह सुनिश्चित होता दिख रहा है कि दोनों देश परस्पर विश्वास, सहायता एवं समर्पण की परिधि को सुदृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सदैव कटिबद्ध रहेंगे। इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

पुतिन के दौरे का सामरिक-आर्थिक महत्व

विश्लेषण
रवि शंकर
स्वतंत्र पत्रकार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिवसीय भारत दौरा और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई दिल्ली और मॉस्को के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह यात्रा न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मंच है, बल्कि यह दर्शाती है कि दबाव के बावजूद दोनों देशों के बीच की साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह भारत को वैश्विक मंच पर बहु-ध्रुवीय नीति पर चलने की ताकत देती है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिवसीय भारत दौरा और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई दिल्ली और मॉस्को के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह यात्रा न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मंच है, बल्कि यह दर्शाती है कि दबाव के बावजूद दोनों देशों के बीच की साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। पुतिन का यह दौरा न केवल पारंपरिक ऊर्जा जैसे तेल, गैस और रक्षा सहयोग तक सीमित है, बल्कि आर्थिक, तकनीकी, स्वास्थ्य, कृषि जैसे कई मोर्चों पर दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाने की एक बड़ी योजना है। इस दौरान दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। पुतिन के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मजबूत आर्थिक साझेदारी के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने और व्यापार घाटे पर भारत की चिंताओं को दूर करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कुल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यूक्रेन में युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

आर्थिक साझेदारी महत्वपूर्ण

मोदी और पुतिन के बीच शिखर वार्ता का मुख्य बिंदु तेल और रक्षा के पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग से हटकर आर्थिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बनाना था, हालांकि पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर रूस के साथ अपने संबंधों को कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा था। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने आठ दशक से अधिक पुरानी भारत-रूस मित्रता को नई गति देने के अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मित्रता ''ध्रुव तारे'' की तरह अडिग बनी हुई है। व्लादिमीर पुतिन का यह भारत दौरा केवल एक मुलाकात भर नहीं, बल्कि यह दोनों देशों के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह विश्व के बदलते समीकरण को भी नए सिरे से परिभाषित करने का काम करेगा। दरअसल, भारत पश्चिमी मुल्कों को यह संदेश देना चाह रहा है कि यह किसी के दबाव में विदेश नीति का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी ध्रुव का हिस्सा है। वहीं, दूसरी ओर पुतिन चीन को यह बतलाना चाह रहे हैं कि रूस केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि वह विकल्पों की तलाश में है।

पश्चिम के देश असहज

अहम बात यह है कि बदलते वक्त के दौर में भी भारत और रूस एक-दूसरे के करीब नजर आए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की सबसे दुर्लभ विदेश यात्राओं में से एक है। पिछले तीन वर्षों से अमेरिका और यूरोप पुतिन को वैश्विक मंच से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जब पुतिन का 'रेड कार्पेट' वेलकम करता है, तो पश्चिमी देशों की यह मुहिम कमजोर साबित होती दिखती है। रूस से भारत के संबंधों को लेकर पश्चिम के देश असहज भी रहते हैं। पश्चिमी देशों की कोशिश है कि पुतिन को अलग-थलग कर दिया जाए। लेकिन भारत जैसा बड़ा देश पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करता है। तो ऐसे में यूरोप की इस रणनीति पर पानी फिरता दिख रहा है। जब भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश रूस के साथ बड़े समझौता करता है तो इससे बाकी दुनिया में एक संदेश जाता है कि पुतिन विश्व के अहम नेताओं की लिस्ट में शुमार हैं। रूस की इकॉनमी को कमजोर करने के इरादे से यूरोप और अमेरिका ने रूस पर कई बैन लगाए थे। लेकिन भारत सस्ती कीमत पर रूस से कच्चा तेल काफी मात्रा में खरीद रहा है। यूरोप को लगता है कि रूस पर लगे बैन के बावजूद उसे अच्छा-खासा रेवेन्यू मिल रहा है, जिसे वह यूक्रेन युद्ध में खर्च कर रहा है।

यूरोप की रणनीति को धक्का

अमेरिका और यूरोप चाहता है कि रूस से कोई भी देश डिफेंस इक्विपमेंट या हथियारों का कोई कारोबार ना करे। लेकिन हथियारों के मामले में भारत हमेशा से रूस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद खरीदार रहा है। इससे यूरोप की उस रणनीति को धक्का पहुंचता है, जिसमें वह चाहता है कि सैन्य रूप से भी रूस को अलग-थलग कर दिया जाए। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की खुलकर निंदा करें और वह यूरोप के खेमे में आ जाए। लेकिन भारत ने यहां अपनी विदेश नीति का पालन करते हुए इस पर निष्पक्ष रुख रखा। उसने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से दूरी बनाए रखी है और किसी भी पाले में शामिल नहीं हुआ। भारत के इस निष्पक्ष रुख से दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। दरअसल, पश्चिमी देश रूस के खिलाफ पूरी दुनिया को लामबंद करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का भारत दौरा रूस-चीन-भारत के बीच मजबूत होते संबंध का मैसेज देता है। ऐसे में यूरोप के लिए पुतिन के इस दौरे को कूटनीतिक झटके के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर दुनिया भर की नजर मोदी और पुतिन के बीच होने वाली बातचीत पर रही जिसमें दोनों नेताओं ने आठ दशक से अधिक पुरानी भारत-रूस मित्रता को नई गति प्रदान करने की अपनी दृढ़ इच्छा प्रदर्शित की। भारत, रूस और चीन का करीब आना अमेरिका के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता है। अमेरिका ने उन देशों पर करीबी से निगरानी की जो रूस से तेल, गैस या अन्य संसाधन लेते हैं। इन सबके बाद भी भारत ने रूस से लगातार तेल खरीदना जारी रखा। यह सब अमेरिका और पश्चिमी देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ब्रिक्स में नई करेंसी की बात करना और अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत का लगातार रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने भारत के ऊपर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इन सब चुनौतियों के बाद भी भारत और रूस का करीब आना एक नए ग्लोबल शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के लिए राष्ट्रहित अहम

यह स्पष्ट करता है कि भारत पश्चिम के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। भारत की विदेश नीति के केंद्र में उसके राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास प्राथमिकता में हैं। इन सबके बीच पुतिन की भारत यात्रा एक बड़े वैश्विक बदलाव की ओर इशारा करती है। अमेरिका को यह डर है कि भारत रूस संबंधों में मजबूती, रूस, चीन और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का काम करेगी। इससे भविष्य में अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है, वह कमजोर हो सकता है। यह यात्रा केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करने से कहीं अधिक है, यह एक रणनीतिक आश्वासन है। यह भारत को वैश्विक मंच पर बहु-ध्रुवीय नीति पर चलने की ताकत देती है।

हैदराबाद हाउस से उठती कूटनीति की गूंज

समीकरण
कांतिलाल मांडोत
स्वतंत्र पत्रकार

हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात सिर्फ दो राष्ट्राधिकारियों का औपचारिक संवाद नहीं था, बल्कि एक ऐसे वक्त में हुई ऐतिहासिक बैठक थी जब वैश्विक राजनीति कई मोर्चों पर तीव्र परिवर्तन से गुजर रही है। विश्व व्यवस्था के बदलते समीकरण, यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि, अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों का बढ़ता दबाव, एशिया की नई रणनीतिक प्राथमिकताएं आदि इन सभी के बीच पुतिन का भारत आना और भारत द्वारा अपनी कूटनीतिक स्थिति स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इस उच्चस्तरीय मुलाकात में भारत ने यह दो टूक कहा कि वह न्यूट्रल नहीं है, बल्कि शांतिपक्ष में है। यह बयान अपने आप में भारत की परिपक्व, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विदेश नीति का परिचायक है। भारत ने दुनिया को संकेत दिया कि वह किसी खेमे की राजनीति में नहीं बँधने वाला, बल्कि उसकी प्राथमिकता वैश्विक शांति, स्थिरता और संवाद है। यही भारतीय विदेश नीति की वह धारा है जिसने दशकों से भारत को वैश्विक मंच पर विश्वसनीय, संतुलित और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि पुतिन ने खुलकर कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी जैसे नेता हैं और उन्होंने यूक्रेन संकट में भारत की शांति कोशिशों की सराहना की। पुतिन का यह औपचारिक आभार न केवल हिंद-रूसी रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत आज उस स्थिति में है जहाँ विश्व की प्रमुख शक्तियां उसकी मध्यस्थता, उसके संवाद और उसके रुख को गंभीरता से सुनती हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। यह सम्मान उस गहरे द्विपक्षीय भरोसे और परंपरा का प्रतीक है जिसने दोनों देशों को दशकों से जोड़ा हुआ है। पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यह कदम न केवल भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि वैश्विक संघर्षों के बीच गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी समाधान का मार्ग हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। यह शब्द केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है। ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों में रूस के साथ संवाद सीमित हो गया है, भारत का यह रुख उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रमाण है। यह भारत की उस भूमिका को भी रेखांकित करता है जो वह वैश्विक शांति के लिए निभा सकता है। पुतिन का यह दौरा अमेरिकी और पश्चिमी दबावों के बीच हुआ। लेकिन भारत ने जिस सहजता, गरिमा और स्पष्टता के साथ अपनी स्थिति रखी, वह उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है।

भारत ने दुनिया को संकेत दिया कि वह किसी खेमे की राजनीति में नहीं बंधने वाला, बल्कि उसकी प्राथमिकता वैश्विक शांति, स्थिरता और संवाद है।

भारत और रूस के बीच अहम डील

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं।

- भारत सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच एक राज्य के नागरिकों की दूसरे राज्य के क्षेत्र में अस्थायी श्रम गतिविधि पर समझौता।
- भारत और रूस के बीच अनियमित प्रवासन से निपटने में सहयोग पर समझौता।
- भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- भारत और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और मानव कल्याण पर निगरानी हेतु संघीय सेवा (रूसी संघ) के बीच समझौता।
- ध्रुवीय जल में परिचालन करने वाले जहाजों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर भारत गणराज्य सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता।
- भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के समुद्री बोर्ड के बीच समझौता।
- मेसर्स जेएससी यूरालकेम और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड के बीच समझौता।
- भारत और रूसी संघ के बीच माल और वाहनों के आवागमन के संबंध में आगमन-पूर्व सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग के लिए भारत गणराज्य सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और संघीय सीमा शुल्क सेवा (रूसी संघ) के बीच प्रोटोकॉल।
- भारत के संचार मंत्रालय के डाक विभाग और जेएससी रूसी पोस्ट के बीच द्विपक्षीय समझौता।
- रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे और संघीय राज्य स्वायत्त उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान श्नेशनल टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, टॉम्स्क के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग पर समझौता।
- मुंबई विश्वविद्यालय, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की संयुक्त स्टॉक कंपनी प्रबंधन कंपनी के बीच सहयोग के संबंध में समझौता।
- प्रसार भारती, भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गजप्रोम-मीडिया होल्डिंग, रूसी संघ के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता।

कार्टूनिस्ट की नजर में ...

भारत ने दिया दोस्ती, सार्वभौमिकता और खुदमुख्तारी का सन्देश

कूटनीति
सुनील अमर
स्वतंत्र पत्रकार

रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पूरी कर जा चुके हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं यानी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमन्त्री मोदी के बीच खूब गर्मजोशी दिखाई पड़ी और पुतिन की अगवानी करने के लिए तो प्रधानमन्त्री मोदी ने निर्धारित प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया, जैसा कि वे इसके पहले भी कई बार अन्य शासनाध्यक्षों की अगवानी के लिए कर चुके हैं। पुतिन की इस यात्रा से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसका तो अभी आने वाले दिनों में गुणा-भाग किया जाएगा लेकिन फिलहाल यह यात्रा अपने प्राथमिक उद्देश्य में सफल कही जा सकती है। भारत अगर अमेरिका की तनी हुई भौंहों की उपेक्षा करने में सफल रहा तो रूस भी पश्चिमी देशों को ठेंगे पर लेने और भारत में अपना बाजार बढ़ाने के प्रयासों में सफल रहा। प्रधानमन्त्री मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दुनिया को सन्देश दिया कि वैश्विक मंच पर भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत हमेशा शान्ति का तरफदार रहा है। थोड़ा गहराई में जाएं तो पाएंगे कि इस तरह की यात्रायें, जितना राजनीतिक दिखायी पड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा कूटनीतिक और व्यापारिक होती हैं। इस यात्रा का भी लब्बोलुआब कूटनीति और व्यापार ही रहा है। यूक्रेन से हो रहे युद्ध में पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाकर उसे अलग-थलग और आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की है और अमेरिका तो रूस के लिए आग बबूला हुआ बैठा है।

ऐसे में रूस को अपना काम-धंधा चलाने और यूक्रेन से लड़ाई लड़ने की दो गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में रूस के दो पुराने मित्र भारत और चीन ने निश्चित तौर पर उसे व्यापारिक सहारा दे रखा है। भारत आने से पहले मार्च 2024 में पुतिन ने चीन का भी राजकीय दौरा किया था। भारत और रूस के कई दशक पुराने द्विपक्षीय सम्बन्ध और समझौते रहे हैं। ध्यान रहे कि कोई भी रूसी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया है। ऐसा लगता है कि वर्ष 1979 से 1989 के बीच अफगानिस्तान में रूसी दखल के समय पाकिस्तान ने अमेरिकी मदद खाकर रूस का जो विरोध किया था, उसको रूस अभी तक भूल नहीं पाया है। भारत और रूस की इस 23वीं शिखर बैठक में जो अहम समझौते किए गए हैं, उनमें एक-दूसरे से सहयोग के अलावा मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और उसके मानक, पर्यटन, पोलर शिप्स, मैरीटाइम कोओपरेशन तथा रासायनिक उर्वरक आदि बताये जा रहे हैं। असल में भारत रूसी सामानों और उत्पादों का बहुत बड़ा ग्राहक है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत-रूस के बीच लगभग 68.7 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। इसमें चिन्ताजनक बात यह है कि रूस ने तो हमको 63.84 अरब डॉलर का सामान बेचा है लेकिन भारत से सिर्फ 05 अरब डॉलर का ही सामान खरीदा है! ऐसे में यह बहुत बड़ा व्यापार असंतुलन का विषय है। देखना होगा कि वर्ष 2030 तक इस द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की जो योजना बनाई गई है, उसमें भारत का निर्यात कितना बढ़ता है। भारत कृषि, दवा, उपभोक्ता सामान, कपड़ा तथा औद्योगिक सामाग्री का बड़े पैमाने पर रूस को निर्यात कर सकता है। अभी तो इस आपसी व्यापार में तसल्ली की बात यही कही जा सकती है कि रूस भारतीय मुद्रा में भी कुछ भुगतान स्वीकार करता है।

देखना होगा कि वर्ष 2030 तक इस द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की जो योजना बनाई गई है, उसमें भारत का निर्यात कितना बढ़ता है।

रूसी रक्षा उत्पादों का भारत बहुत पुराना और बड़ा ग्राहक है। इस बार भी रक्षा सम्बन्धी कुछ सौदे हुए हैं लेकिन यूक्रेन युद्ध के समय से ही रूस पर जो आर्थिक प्रतिबन्ध लगे हैं, उससे उसकी उत्पादन क्षमता और व्यवस्था प्रभावित हुई है और वह निश्चित समय पर अपने व्यापार करार पूरे नहीं कर पा रहा है। भारत को खासकर रूसी रक्षा सौदों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है कि आपूर्ति समय से हो सके। श्रमिकों के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था बनाए जाने की बात कही गई है। इसमें अत्यन्त सावधान रहने की जररूरत है क्योंकि भारत से गए श्रमिकों को कथित तौर पर रूस में युद्ध के मैदान में लगा दिया गया था और अभी भी कुछ श्रमिक वहां फंसे बताये जा रहे हैं। भारत और रूस ने वर्ष 1971 में मित्रता और आपसी सहयोग को लेकर 20 वर्षों के लिए एक बड़ी शान्ति सन्धि की थी। यह रिश्ता आज तक चला आ रहा है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत के लिए अमेरिका के मुकाबले रूस ज्यादा भरोसेमन्द है। अभी सम्पन्न 23वीं शिखर बैठक ने इस भरोसे को और आगे बढ़ाया है। हालांकि पुतिन के भारत आने से ऐन पहले ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के भारत स्थित राजदूतों ने अंग्रेजी दैनिक में एक संयुक्त लेख लिखकर रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा कई यूरोपियन देशों ने अपरोक्ष तौर पर भारत से आग्रह किया था कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव बनाये। उधर अमेरिकी मीडिया और विश्लेषकों ने इस बैठक को इस भाव में लिया कि पुतिन यह दिखाना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों द्वारा उनके देश पर लगाये गए आर्थिक प्रतिबन्धों और उसे अलग-थलग करने की कोशिशों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि 'सैंक्शन्स किंग' ट्रम्प इसको किस निगाह से देख रहे हैं।

शाह ने गुजरात में बायो-सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का किया लोकार्पण

डेयरी क्षेत्र के लिए कई योजनाएं चल रहीं, इस उद्योग को मिलेगी मजबूती

नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रखी नींव

नई दिल्ली,

गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के वाव-थराड़ क्षेत्र में बनास डेयरी द्वारा स्थापित नए बायो-सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले दूध पाउडर संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता, जिनमें गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा मुरलीधर मोहोल उपस्थित रहे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, संशोधित राष्ट्रीय डेयरी योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसी बड़ी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जो देश के डेयरी उद्योग को नई मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि बनास डेयरी का बायो-सीएनजी मॉडल देशभर की अन्य सहकारी समितियों के लिए प्रेरणा बनेगा।

गुजरात के वाव-थराड़ क्षेत्र को दी सौगात

कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण करते गृहमंत्री शाह

बनास डेयरी के लिए महिलाओं को दिया श्रेय

शाह ने बताया कि बनास डेयरी का कारोबार अब 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इस सफलता का बड़ा श्रेय बनासकांठा की महिलाओं को जाता है, जिन्होंने दूध संग्रह और सहकारी मॉडल को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। देशभर के लगभग 250 डेयरी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जनवरी में बनासकांठा का दौरा करेंगे ताकि इस सहकारी मॉडल को करीब से समझ सकें। नर्मदा और माही नदियों से जल लाने वाली परियोजनाओं के कारण बनासकांठा में बड़ा परिवर्तन आया है।

उन्होंने 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले दूध पाउडर संयंत्र की आधारशिला भी रखी

गोबर और डेयरी अपशिष्ट से किसानों की आय बढ़ेगी

इससे गोबर और डेयरी अपशिष्ट से जैव-उर्वरक, बायोगैस और बिजली तैयार होगी और किसानों की आय में कम से कम 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव होगी। शाह ने यह भी घोषणा की कि अब सहकारी डेयरियां अपना पशु-चारा स्वयं तैयार करेंगी ताकि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने अमूल को उच्च मूल्य वाले डेयरी उत्पादों की सूची भी भेजी है, ताकि वैश्विक बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीज, जैविक उत्पाद और कृषि निर्यात के लिए तीन नए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठन बनाए हैं तथा तीन बहुराज्यीय डेयरी सहकारी समितियों को भी स्थापित किया है।

यह 400 रुपए से शुरू होकर 24 हजार करोड़ के कारोबार तक पहुंची

शाह ने एशिया की सबसे बडी बनास डेयरी को सहकारिता का सफल माडल बताते हुए कहा कि यह डेयरी 400 रुपए से शुरू होकर 24 हजार करोड़ के कारोबार तक पहुंची है। यह सफलता किसानों और पशुपालकों की मेहनत का परिणाम है।शाह ने विश्वास जताया कि आगामी पांच वर्षों में पशुपालकों की आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।शाह ने शनिवार को बनास डेयरी के अध्यक्ष एवं गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत की और बनास डेयरी की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

नागरिकों से मिलते गृहमंत्री शाह

मिलकर काम करने का आह्वान किया

उन्होंने श्वेतक्रांति 2.0 को सफल बनाने और 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। शाह ने वाव-थराद जिले के सणादर डेयरी में बनास रेडियो स्टेशन, पोटैटो प्लांट और आइसक्रीम प्लांट का निरीक्षण किया।

दुग्ध समितियों में माइक्रो-एटीएम स्थापित किए गए

उन्होंने बताया कि गांव-गांव की दूध समितियों में माइक्रो-एटीएम स्थापित कर दिए गए हैं और भविष्य में इनके माध्यम से अन्य वित्तीय सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी। कार्यक्रम के दौरान शाह ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी और सरदार वल्लभभाई पटेल के सहकारी आंदोलन में योगदान को भी याद किया।

राजस्थान में पहली बार कानून लागू

फाइल फोटो।

अगर शव रखकर प्रदर्शन किया तो अब होगी पांच साल जेल

नई दिल्ली,

राजस्थान में अब मृतक शरीर को रखकर विरोध प्रदर्शन करना, लाश पर राजनीति करना और बिना वजह अंतिम संस्कार में देरी करना अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित 'मृतक शरीर सम्मान कानून' के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं। नियम लागू होने के बाद अब इस कानून के तहत सीधे कार्रवाई की जा सकेगी। 20 जुलाई 2023 को पिछली गहलोत सरकार के दौरान यह बिल पारित हुआ था। 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 अगस्त 2023 से यह कानून प्रभावी हो गया था, लेकिन इसके नियम जारी नहीं हुए थे। उस समय विपक्ष में रही बीजेपी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने बिना बदलाव किए ही इसके नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

परिजनों पर हो सकेगी कार्रवाई

अगर परिजन राजनीतिक या सामाजिक दबाव के लिए डेड बॉडी नहीं उठाते, तो उन्हें भी सजा मिलेगी। किसी भी नेता, संगठन या गैर-परिजन द्वारा शव के साथ विरोध करने पर भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

नियम अधिसूचित होने के बाद अब इस कानून के दायरे में परिजन, नेता और मामले से जुड़े सभी व्यक्ति आ जाएंगे। डेड बॉडी का उपयोग कर विरोध, राजनीति या सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने की किसी भी कोशिश पर सीधे कार्रवाई की जा सकेगी।

अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य

नियमों के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य होगा। देरी सिर्फ मृतक के परिजन बाहर से आ रहे हों या फिर पोस्टमॉर्टम आवश्यक हो इन्हीं परिस्थितियों में ही मान्य होगी, अन्यथा पुलिस मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। नए प्रावधानों के अनुसार डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करने, सड़क जाम करने या लाश के जरिए दबाव बनाने पर 1 से 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माना लगेगा।

भारत मंडपम में 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर

एआई और मशीन लर्निंग देश के विद्युत नेटवर्क को बदल देगी

विद्युत व्यवस्था होगी तेज और उपभोक्ताओं का अनुभव भी बेहतर होगा

नई दिल्ली,

केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकें आने वाले समय में भारत के विद्युत वितरण तंत्र को पूरी तरह बदल देंगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बताया कि ये तकनीकें बिजली नेटवर्क को अधिक स्मार्ट, उपभोक्ता-केंद्रित और स्वयं अनुकूल बनने में मदद करेंगी। उनके अनुसार एआई और मशीन लर्निंग से विद्युत व्यवस्था न केवल तेज होगी, बल्कि उपभोक्ताओं का अनुभव भी बेहतर होगा। खट्टर ने "स्टैलर" नामक संसाधन पर्याप्तता योजना उपकरण को भी लॉन्च किया

स्टैलर संसाधन पर्याप्तता योजना भी लॉन्च

कटौतियां कम होंगी और लागत में भी कमी आएगी

खट्टर ने बताया कि स्मार्ट मीटर विश्लेषण, डिजिटल ट्विन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, बिजली चोरी का पता लगाने वाली प्रणाली, उपकरण-स्तर की बिजली खपत की जानकारी, आउटेज पूर्वानुमान और जनरेटिव-एआई आधारित निर्णय-सहायता जैसे समाधानों से वितरण कंपनियों की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ सकती है। इन तकनीकों के इस्तेमाल से उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली मिलेगी।

गलतफहमियों और अफवाहों

खट्टर ने सभी वितरण कंपनियों, तकनीकी भागीदारों, नवाचारकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को लेकर फैल रही गलतफहमियों और

एमपी ईस्ट 'डिसकॉम' श्रेणी में विजेता बना

इस सम्मेलन में राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के तहत 195 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें वितरण कंपनियां, एडवांस मीटरिंग सेवा प्रदाता, टेक्नोलॉजी कंपनियां और होम-ऑटोमेशन संस्थाएं शामिल थीं। कई चरणों की जांच के बाद तमिलनाडु की टीएनपीडीसीएल और मध्य प्रदेश की एमपी ईस्ट को 'डिसकॉम' श्रेणी में विजेता चुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

ईश्तहार

ग्राम पंचायत सेन्दूर चौकी तातापानी थाना रामानुजगंज तहसील बलरामपुर

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

एतद द्वारा सर्वसाधारण ग्राम पंचायत सेन्दूर को सूचित किया जाता है। कि आवेदक सुकूल यादव पिता जगत यादव निवासी ग्राम सेन्दुर चौकी तातापानी थाना रामानुजगंज तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा अपना नाम ओमकेश्वर यादव से परिवर्तित कर नया नाम सुकूल यादव के नाम से समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकाय, बैंकिंग अभिलेख राजस्व अभिलेख आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज व प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदन पत्र के आधार पर हल्का पटवारी, पटवारी हल्का नंबर 09. तहसील बलरामपुर से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। आवेदक का त्रुटिवश आधार कार्ड में ओमकेश्वर यादव पिता जगत यादव हो गया है। आवेदक का नाम सुकूल यादव ही है। एवं वर्तमान में आवेदक सुकूल यादव पिता जगत यादव का निवास ग्राम पंचायत सेन्दुर में मकान बनाकर निवासरत है।

यदि उत्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 17/12/2025 को अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त नियत समयावधि के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक/7/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बलरामपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र /अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार अग्रवाल पिता खजांचीलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी ब्रम्हरोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 2794/9. 2794/10 रकबा 0.007, 0.006 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो. तो निर्धारित सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के साध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 8/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा), अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०..अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेंन्द्र यादव पिता देवराज जाति अहीर निवासी जरही तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम गंगापुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 299/80 रकबा 0.020 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

शपथ पत्र

मै प्रेमशीला चौहान पिता स्व. नाकाराम चौहान उम्र करीब 34 वर्ष, जाति गांड़ा निवासी ग्राम इंजको थाना व तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर ही निवासी होकर निम्न कथन शपथ पूर्वक करता हूँ, 1/ यह कि मुझे अपने भतीजा अयांश चौहान पिता स्व. रविन्द्र चौहान के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अमाश चौहान माता का नाम दुवसा बाई एवं जन्म तिथि 01/01/2012 दर्ज किया गया है जिसे सुधार कर संसोधन करने हेतु शपथ पत्र निष्पादित करने की आवश्यकता हुई है। 2/ यह कि मेरे भतीजा का वास्तविक नाम अयाश चौहान AYANSH CHAUHAN पिता स्व. रविन्द्र चौहान (RAVINDRA CHAUHAN) एवं माता का नाम अशील्या चौहान (ASHILYA CHAUHAN) एवं वास्तविक जन्म तिथि 10/08/2011 दर्ज करने हेतु शपथ पत्र निष्पादित कर रही हूँ। 3/ यह कि उक्त शपथ पत्र के आधार पर मेरे भतीजा का आधार कार्ड में संसोधन कर त्रुटिपूर्ण नाम के स्थान पर वास्तविक नाम अयांश चौहान पिता स्व. रविन्द्र चौहान एवं माता का नाम अशील्या चौहान एवं जन्म तिथि 10/08/2011 दर्ज करने का निवेदन है।अतः शपथ पत्र लिख दी जो सनद रहे व समय पर काम आवे।

शपथ कर्ता

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र /अ-2/2025-26

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुनम शुक्ला पत्नी मुकेश शुक्ला जाति ब्राहम्ण निवासी शिवधारी कालोनी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग0) खसरा नंबर 127/1, 127/2 रकबा 0.220, 0.230 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन पूर्व में हो चुका है। उका भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारधीन है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या सस्था को कोई आपत्ति हो, तो निधर्धारित सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथदा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया

अनुविभागीय अधिकारी
(रा). अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

ईश्तहार :-

रा०प्र०क्र०-/-6/2026-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मंजू सोनी पत्निः सम्पत सोनी, उम्र 47 वर्ष, जाति सोनार, निवासी जोडापीपल रोड, महाराजा गली अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक रामचन्द्र अग्रवाल आ.स्व. सेठ मातुराम अग्रवाल, उम्र 74 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी देवीगंज रोड, महाराजा गली अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के स्वामित्व व आधिपत्य की शीट नं. 03. मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लॉट नं 1073/1 रकबा 6098 वर्गफीट में से रकबा 26.540= 1060 वर्गफीट भूमि की पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 04/11/2025 के माध्यम से क्रम किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त नजूल भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु आवेदिका द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति गय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या सस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19/12/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05/12/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा० प्र०क्र० ब/121

ग्राम कल्याणपुर प.ह.न....

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम सिंह मानिकपुरी आङ्ग स्व. जगमोहन मानिकपुरी जाति पनिका निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व0 जगमोहन का मृत्यु दिनांक 12-11-2014 को ग्राम कल्याणपुर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कल्याणपुर आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनाक 23/12/2025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 05/12/2025 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
तहसील लटोरी जिला सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

रा०प्र०क०ब-121/2024-25

ग्राम चन्द्रगढ़

तहसील राजपुर

-::ईश्तहार::-

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम चन्द्रगढ़ को सूचित किया जाता है कि आवेदक वितना आ० झलका जाति गोड निवासी ग्राम चन्द्रगढ़ थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) द्वारा अपने पत्नी सा बान्दो पति वित्तना की मृत्यु ग्राम चन्द्रगढ़ में दिनांक 14/05/2024 को हुआ है। में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अनिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 15/12/2025 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया

कार्यपालिक दंडाधिकारी
राजपुर, जिला बलरामपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र...../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो० सहिम आ० स्व० सिद्दीक अंसारी जाति जुलाहां निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 84/5 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा), अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनवन हुसैन आ० सफीक अंसारी जाति जुलाहा निवासी मोमिनपुरा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम श्रीगढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 102/16, 103/1 रकबा 0.002, 0.014 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अत्तएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा), अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नितिग्य जायसवाल पिता प्रमोद जायसवाल जाति कलंवार निवासी जोड़ा पीपल अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 185/28 रकबा 0.012 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, ले-आउट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 23/12/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा), अम्बिकापुर

आज की हाईटेक दुनिया में मानवाधिकार, सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है। आपकी ऑनलाइन आदतों, व्यवहार और दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता में भी यह प्रकट होता है। यहां बताई जा रही आदतों को अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति न सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में खुद को सुरक्षित रख सकता है बल्कि दूसरों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में योगदान भी कर सकता है।

डिजिटल वर्ल्ड में भी जरूरी है
मानवाधिकारों के प्रति सजगता

कवर स्टोरी

लोकमित्र गौतम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-स्पीड इंटरनेट और 24X7 स्क्रीन-लाइफ के इस दौर में मानवाधिकारों की परिभाषा वह नहीं रही, जो बीसवीं सदी के मध्य या उत्तरार्द्ध में हुआ करती थी। जीवन जीने की नई चुनौतियों के बीच, जीवन के अधिकारों की जमीन भी बदल रही है। साथ ही सार्वभौम मानवाधिकारों की परिभाषा भी बहुत तेजी से बदल रही है। आज मानवाधिकारों के दायरे में सिर्फ आपकी सदेह उपस्थिति ही नहीं रही, बल्कि डिजिटल उपस्थिति, ऑनलाइन व्यवहार और टेक्नोलॉजी के प्रयोग भी आ गए हैं। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट, डिजिटल जीवनशैली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बीच बड़ी हुई पीढ़ी है। इसलिए उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों का दायरा भी इन सभी आयामों से जुड़ता है। डिजिटल दुनिया की संवेदना का सम्मान किए बिना आज मानवाधिकारों की चर्चा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आज इंसान के जीवन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटलाइज हो चुका है। इसलिए इस जीवन की हिफाजत, उसका सम्मान और उसकी संवेदनशीलता का ख्याल रखना भी आज का मानवाधिकार है।

महत्वपूर्ण है डिजिटल प्राइवेसी: डिजिटल स्पेस में प्राइवेसी का अर्थ सिर्फ 'सीक्रेट' रखना नहीं है बल्कि अपनी पहचान, आदतों और भावनाओं को सुरक्षित रखना भी है। हर मोबाइल एप आज आपके व्यवहार पर गहरी नजर रखता है और आपकी एक डिजिटल कुंडली बनाता है। उसे आपकी लोकेशन से लेकर आपकी हार्टबीट तक पता होती है। ऐसे में एक जागरूक युवा वही है, जो हर अनुमति को ध्यान से पढ़ता है, अपनी डिजिटल दुनिया के दरवाजों का मजबूत पासवर्ड रखता है, टू-फैक्टर सुरक्षा अपनाता है और अपनी निजी जानकारियां केवल जरूरी और सुरक्षित मंचों पर ही साझा करता है। लब्बोलुआब यह कि जो युवा अपनी प्राइवेसी की कीमत समझता है, वही दूसरों की प्राइवेसी का अर्थ भी जानता है। इसलिए मानवाधिकारों के प्रति सजग बनना है तो डिजिटल प्राइवेसी का सम्मान करना और इसे खुद भी सीखना जरूरी है।

साइबर बुलिंग का विरोध: स्मार्टफोन के दो क्लिक किसी की मानसिक शांति छीन सकते हैं। बॉडी-शेमिंग, ट्रोलिंग, मीम के नाम पर अपमान- ये सब मनोरंजन नहीं है बल्कि डिजिटल हिंसा है। एक संवेदनशील और मानवाधिकारों के लिए सजग युवा वही है, जो ऐसी हरकतों पर चुप नहीं रहता। 'रिपोर्ट' करता है, 'ब्लॉक' करता है और पीड़ित को 'सपोर्ट' करता है। ये तीन शब्द आज की सामाजिक जिम्मेदारी हैं। किसी की मानसिक भलाई भी एक मानवाधिकार है और इस भलाई को करना हर युवा के डिजिटल नागरिक होने का कर्तव्य भी है। इसलिए मानवाधिकारों का चैंपियन बनने के लिए इन सब हरकतों को लेकर चुप नहीं रहना चाहिए।

ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा का अधिकार

यूपीआई, वॉलेट पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग ने सुविधा बढ़ाई है, लेकिन जोखिम भी बढ़ाया है। डिजिटल धोखाधड़ी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक क्षति भी है। इस मामले में आप अपने मानवाधिकारों को तभी तक सुरक्षित रख सकते हैं, जब तक अजनबियों को ओटीपी, पिन, पासवर्ड नहीं बताते, संदिग्ध लिंक नहीं खोलते, क्यूआर कोड बिना सोचे नहीं स्कैन करते। वित्तीय सुरक्षा, आधुनिक मानवाधिकारों में सीधे इस सोच से जुड़ी है कि आर्थिक स्वाभिमान भी एक अधिकार है।

कुछ भी शेयर करने से पहले: किसी की फोटो, चैट, स्क्रीनशॉट या किसी की वीडियो को फटाफट पब्लिक फ्रंट पर साझा करने से पहले न केवल कई बार सोचें बल्कि जिनसे सीधे उसका रिश्ता है, अनिवार्य रूप से उसकी सहमति भी लें। अगर सहमति मिलती है, तभी सार्वजनिक दुनिया में प्राइवेसी के इन खास पलों को साझा करें। अगर ऐसा नहीं करते तो इससे साबित होगा कि आप डिजिटल दुनिया में न तो सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हैं और न ही लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। क्योंकि जो खिलवाड़ आप हंसी खेल में कर देंगे, वो किसी के लिए अभिशाप भी बन सकता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए 'कंसेंट कल्चर' सिर्फ भौतिक रिश्तों में ही नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी जरूरी है। दूसरों की अनुमति का सम्मान करना डिजिटल नैतिकता का आधार है।

फेक न्यूज-हेट स्पीच से दूरी: डिजिटल वर्ल्ड में मानवाधिकारों के प्रति अगर आप सजग हैं तो न सिर्फ फेक न्यूज और हेट स्पीच से दूर रहना जरूरी है बल्कि उन्हें हर संभव तरीके से रोकना भी जरूरी है। एक जागरूक डिजिटल यूजर को इसे भी अपनी 'नेट नागरिकता' की जिम्मेदारी और मानवाधिकार मानना चाहिए, क्योंकि भ्रामक खबरें अब खतरनाक हथियार बन चुकी हैं। एक एडिटेड वीडियो, एक गलत जानकारी पूरे समुदाय को तनाव में ला सकता है, अराजकता फैला सकता है। अतः जिम्मेदार और डिजिटल युग में मानवाधिकार के प्रति सजग वही है, जो किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचे। याद रखिए हेट स्पीच 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' नहीं है बल्कि यह स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण है। इसे रोकना डिजिटल समाज को सुरक्षित बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

डेटा उपयोग को जानने का अधिकार: आज आपके सोशल मीडिया फीड में क्या दिखेगा, यह आपकी पसंद से ज्यादा एल्गोरिद्म तय करता है। एआई आपकी आदतों का विश्लेषण करता है और आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। हर डिजिटल सजग युवा को यह जानने का अधिकार है कि उसका डेटा कैसे उपयोग हो रहा है? इसके प्रति सजग और संवदनेशील बने रहना जरूरी है।

मानसिक स्वास्थ्य का मानवाधिकार: डूम-स्क्रॉलिंग, लाइक्स पर निर्भरता, दूसरों की तुलना में आत्म-मूल्य घटाना, ये नई डिजिटल बीमारियां हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी मानवाधिकार है और उसकी रक्षा आपको स्वयं करनी होती है। स्क्रीन टाइम सीमित करना, डिजिटल डिटॉक्स, सकारात्मक सामग्री चुनना और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगना, आपको मजबूत और संतुलित बनाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने अधिकारों के लिए सजग रह सकता है।

डिजिटल फुट प्रिंट की समझ: इस बात को याद रखिए कि इंटरनेट कुछ भूलता नहीं। सोशल मीडिया पर डाला गया हर शब्द, हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अपने या अपने दोस्त के प्रति एक लापरवाही, करियर, रिश्तों या छवि पर भारी पड़ सकती है। इसलिए हर पोस्ट से पहले सोचना जरूरी है कि क्या ये भविष्य में मुझे या मेरे जैसे किसी और को चोट तो नहीं पहुंचाएगी? डिजिटल फुट प्रिंट का ध्यान रखना एक समझदार, संवेदनशील और भविष्य-दृष्टि वाला डिजिटल सिटिजन बनने का सबसे आसान तरीका है।

स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार: सभ्य संवाद ही आधुनिक अधिकार संस्कृति है। ऑनलाइन बोलने का साहस अच्छा है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता, तर्क और शिष्टता भी होनी चाहिए। मतभेद स्वाभाविक हैं पर अपमानजनक भाषा मानवाधिकार मूल्यों को तोड़ती है। एक परिपक्व व्यक्ति वही है, जो अपनी राय साफ रखता है, लेकिन किसी की गरिमा को चोट नहीं पहुंचाता। *

स्वास्थ्य मात्र सुविधा ही नहीं
हम सभी का है अधिकार

कोई भी देश-समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता, खुश नहीं रह सकता, जब तक वहां के लोग स्वस्थ नहीं रहते। इसीलिए लोगों और सरकारों को इस दिशा में अवेयर करने के लिए हर साल 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-डे मनाया जाता है। इस बारे में सभी को पता होना चाहिए।

अवेयरनेस

डॉ. माजिद अलीम

हर साल 12 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाने वाला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-डे, हमें यह याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन का हक, किसी खास वर्ग या आर्थिक स्थिति से नहीं जुड़ा। अस्पताल, दवा, इलाज, टेस्ट, मानसिक स्वास्थ्य- ये सब उपलब्धता का मुद्दा नहीं बल्कि धरती के हर नागरिक का अधिकार हैं।

यह दिन मनाने का मकसद: इस दिन का वास्तव में असली मकसद यही है कि आम लोग अपने नागरिक अधिकार समझें, क्योंकि बीमार होना कभी किसी की गलती नहीं होती, पर इलाज न मिलना व्यवस्था की गलती होती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, दुनियाभर की सरकारों, नीति-निर्माताओं और नागरिकों को यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य पर किया गया निवेश सिर्फ लोगों को मजबूत नहीं बनाता बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और समृद्ध करता है। जब हर व्यक्ति बिना आर्थिक मदद के डॉक्टर तक पहुंच सके, तभी सही अर्थों में, 'हेल्थ फॉर ऑल' जैसा नारा सच होगा।

ऐसे हुई इस दिन की शुरुआत: जहां तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-डे की शुरुआत और इसके मनाए जाने की वजह का सवाल है तो संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक मान्यता इस विशेष दिन के लिए 2017 में मिली। जब दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके 12 दिसंबर को आधिकारिक रूप से यूएचसी डे (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-डे) घोषित किया। यह पहल वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों, नागरिक समाज और विभिन्न देशों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम थी। हालांकि ये 2017 में संभव हुआ, लेकिन इसकी जड़ें 2012 से जुड़ी हैं, जब इसी 12 दिसंबर को यूएन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर पहली बार ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन को ही बाद में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में चुना गया।

कई तरह के होते हैं आयोजन: जहां तक देश और दुनिया में इस विशेष दिन को मनाए जाने के तरीके का सवाल है तो दुनिया के अलग-अलग देश और संस्थाएं इस दिन को कई तरीकों से सेलिब्रेट करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालयों और विभिन्न एनजीओं द्वारा सोशल मीडिया कैंपेन, 'हेल्थ फॉर ऑल', 'यूएचसी डे' जैसे हैश टैग के साथ मनाया जाता है। इस दिन अनेक डिजिटल पोस्टर, वीडियो और जनसंदेश स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। कई जगहों पर स्वास्थ्य शिविर और मुफ्त जांच कार्यक्रम चलते हैं। रक्तदान शिविर, टीकाकरण जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग कैंपेन और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान चलाए जाते हैं।

स्कूल कॉलेज में इस दिन छात्रों के लिए कई तरह की वर्कशॉप लगती हैं। हेल्थ अवेयरनेस रैली निकलती है। निबंध, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं होती हैं तथा मीडिया कवरेज भी इस अवसर को खास तव्वजो देती है। विभिन्न टीवी चैनल और पत्रिकाएं इस दिन के लिए विशेष कार्यक्रम बनाते हैं।

कोविड काल से बढ़ी महत्ता: साल 2019-20 में कोविड महामारी के दौरान इस खास दिन के लिए दुनिया भर में सजगता बढ़ी है, क्योंकि कोविड ने दिखा दिया कि असमान स्वास्थ्य ढांचा सिर्फ उस देश के लिए ही जोखिम भरा नहीं है, जहां ये होता है बल्कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। इसलिए इस दिन देशों को यह याद दिलाया जाता है कि स्वास्थ्य में निवेश करना, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की आधारशिला है। दुनिया में हर साल करीब 10 करोड़ लोग स्वास्थ्य खर्च के चलते गरीबी रेखा से घिर जाते हैं, जबकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की यह धारणा ही है कि स्वास्थ्य लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली चीज नहीं है बल्कि सरकारों की अपनी जनता के लिए बुनियादी जिम्मेदारी है।

सामाजिक जिम्मेदारी है अच्छी हेल्थ: आधुनिक जीवनशैली, बढ़ता स्क्रीन टाइम, तनाव और फास्ट फूड की ललक के चलते दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं का मानव विस्फोट हो गया है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर हर तरफ खतरा और डर महसूस होता है, जिसके कारण अरबों, खरबों डॉलर के हर साल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा लोगों द्वारा लिए जाते हैं। उस सबके बीच यूएचसी डे का कुछ अलग ही महत्व निकलकर आता है कि स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह सामाजिक जिम्मेदारी है। *

नवगीत

घमंडीलाल अग्रवाल

सुख हो गया लघुकथा जैसा

सुख हो गया लघुकथा जैसा
उपन्यास-सा दुख!
पसर गईं हैं मन में आकर
ऐसे इच्छाएं,
वर्षा के मौसम में नभ पर
जैसे घन छाएं।
पढ़े न कोई उर की पोथी
देखें सब आमुख।
भौतिकता की चकाचौंध ने
हमको भरमाया,
आमदनी आठ आने, खर्चा
है रुपया पाया।
उलझन ने खोले सुरसा-से
बड़े-बड़े अब मुख।
माया के चक्कर में काया
हुई सूख कांटा,
परेशानियां सांझ-सकारे
मार रहीं चांटा।
फिर भी खाई में गिरने का
अपनाया है रुख।
हवा भरे गुब्बारों जैसे
लोग नजर आते,
घड़ी दो घड़ी साथ निभाकर
पिचक बाद जाते।
बांह न कोई गहे उम्र भर
कब बैठे सम्मुख।

लघुकथाएं

दीवारें भी कुछ कहती हैं

बाबूजी ने अपने पुराने घर का रेनोवेशन करवाया था। पूरा घर चमकने लगा था। दरवाजों पर सुंदर कलर के पेंट, दीवारों पर नई डिजाइन की कलाकारी, नया पेंट, पुट्टी सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था। यह सब देखकर ससुराल से आई बेटी रानू बहुत खुश हो रही थी। वो घर के अंदर गई तो देखकर दंग रह गई। मुख्य द्वार पर पीले, लाल हाथों के निशान ज्यों के त्यों थे। बैठक में दीवारों पर रंग-बिरंगी आड़ी-तिरछी रेखाएं मुंह चिढ़ा रही थीं। और तो और जीने की दीवारों पर तेल भरे हाथों के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इन सभी जगहों को छोड़कर बाकी दीवारों पर लिपाई-पुताई कर दी गई थी। यह सब देखकर हैरान-सी रानू ने अपने पिता से पूछा, 'बाबूजी, यह सब क्या है? आपने इन दीवारों पर इन गंदे दाग-धब्बों पर पेंट क्यों नहीं करवाया? ऐसे इन्हें क्यों छोड़ दिया? देखो ये कितने बदरंग दिख रहे हैं।'

बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, 'बेटा, यह बदरंग धब्बे-दाग नहीं, यह रिश्तों के प्रेम के खुशरंग निशानी हैं। ये देखो, यह लाल, पीले हाथों के छाप। यह तेरी बुआ के हाथों के छाप हैं, जब वह ससुराल गई थी। ये लाल निशान तेरे हाथों के हैं, जब तू ससुराल गई थी। ये आड़ी-तिरछी रेखाएं तुम सब नन्हे-मुन्ने बच्चों की हैं, जब तुम शरारत करते थे। यह जीने पर तेल के दाग तुम्हारे पूज्य दादा जी के हैं, जब-तब वे जीने पर इन दीवारों के सहारा लेकर चढ़ते थे। आज वे नहीं रहे, पर ये निशानियां हैं, जो मुझे हमारे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। ये दीवारें भी कुछ कहती हैं हमसे, तुम भी सुनो।' बाबूजी की बात सुनकर रानू पुरानी यादों में खो गई। *

- शैल चंद्रा

सीमा

आज डमरू अपनी बिटिया विनी को बाजार में ड्रेस दिलाने लाया था। एक फ्रॉक की दुकान पर दोनों रुक गए।

'पापा..पापा.. ये फ्रॉक ले लो ना.. ये वाली..।' विनी ने मचलते हुए एक फ्रॉक की तरफ इशारा किया। डमरू का दिल धक-धक करने लगा। स्लेटी रंग की वह फ्रॉक सिल्क की थी। उसने सोचा काफी महंगी होगी। डमरू को समझ नहीं आ रहा था, छह साल की बेटी को कैसे बहलाए।

गर्दन घुमाते हुए डमरू को एक रंगीन लेकिन सस्ती सी फ्रॉक दिखाई दी। वह बोला, 'आहा! यह देखो विनी, इसमें झालर है, घुंघरू भी लगे हैं, इसे ले लो बेटा।'

रंग की चकाचौंध में विनी बहल गई। उसने वही फ्रॉक ले ली। सूती कपड़े की रंगीन फ्रॉक पहनकर अगले दिन विनी स्कूल गई। वहां स्कूल फंक्शन में विनी ने कविता प्रतियोगिता में प्यारी सी एक कविता सुनाई। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। विनी की खुशी दोगुनी हो गई।

घर आकर चहकते हुए उसने बताया, 'पापा, इसी प्यारी फ्रॉक की वजह से मिल गया पहला ईनाम।' विनी खुशी से अपनी ट्रॉफी चूम रही थी। डमरू को पिछले साल का वह वाकया याद आया, जब एक मिठाई की दुकान पर काजू कतली को देखकर विनी मचल गई थी, उसे यह मिठाई खानी है। डमरू ने दूसरी तरफ उसे बहलाते हुए रंगीन पेठा दिखाया। मासूम विनी वही रंगीन रसीला पेठा खाकर खुश हो गई थी। कल भी डमरू ने वही किया। विनी तो छोटी बच्ची है, अबोध। लेकिन डमरू मजबूर है, उसे अपनी सीमा का आभास है, वह अपनी चादर से बाहर पैर नहीं फैला सकता। *

-पूनम पांडे

पुस्तक चर्चा / विज्ञान भूषण

स्मृतियों की बस्ती

हाल में वरिष्ठ कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखे गए संस्मरणों की किताब 'स्मृतियों की बस्ती' छपकर आई है। इसमें कुल सोलह संस्मरण संकलित हैं। इनमें त्रिलोचन और अमरकांत पर दो-दो संस्मरण हैं और एक संस्मरण इलाहाबाद में लेखक के द्वारा बिताए गए दिनों पर आधारित है।

'चिड़ियों के घर का वासी' संस्मरण हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा गया है। इसमें लेखक ऐसी छोटी-छोटी कई बातें बताते हैं, जिनसे द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की सहजता और सरलता में निहित विराटता प्रकट होती है। 'बरगद जैसे छायादार थे अमृतलाल नागर' संस्मरण में लेखक ने नागर जी से मिली आत्मीयता का मार्मिकता से वर्णन किया है। अमरकांत पर इस पुस्तक में दो संस्मरण संकलित हैं- 'अशोक वृक्ष की छाया में' और 'अमरकांतः प्रफुल्लता की प्रतिमूर्ति।' त्रिलोचन पर भी पुस्तक में दो संस्मरण 'नाम सार्थक लगे त्रिलोचन' और 'एक विरोधाभास त्रिलोचन' संकलित हैं। काशीनाथ सिंह, हरिशंकर परसाई और बाबा नागार्जुन से जुड़े संस्मरणों में उनके कई अनछुए पहलू उजागर हुए हैं। पुस्तक के अंतिम संस्मरण 'इलाहाबाद के वे दिन' में अब्दुल बिस्मिल्लाह लिखते हैं, 'इलाहाबाद के साहित्यिक-सांस्कृतिक वातावरण, वहां की गतिविधियों, रचनाकारों के जमावड़ों, भांति-भांति के व्यक्तियों और समग्रता में उस शहर के जीवन प्रवाह ने न केवल मेरी जीवनी शक्ति को दृढ़ता प्रदान की, बल्कि मेरी रचनाशीलता को भी धार दी।' बिस्मिल्लाह जी ने जिन हस्तियों पर संस्मरण लिखे हैं, उनके साथ उनके शहर का जीवन स्पंदन और जीवनशैली का सोंधापन भी महसूस कराते चलते हैं। *

पुस्तक: स्मृतियों की बस्ती, **लेखक:** अब्दुल बिस्मिल्लाह, **मूल्य:** 299 रुपए, **प्रकाशक:** राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

चांदनी बिहारपुर क्षेत्र करौटी ए के शराबी शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल

शिक्षक के शराबखोरी से परेशान पंचायत प्रतिनिधियों ने उच्च अधिकारियों से भी की थी शिकायत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला शिक्षा विभाग द्वारा लापरवाह शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है बावजूद इसके कुछ शिक्षक अपनी कारगुजारियों से शिक्षक की छवि धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे है। अभी हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने लापरवाह शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक कार्यवाही कर रहे है। अब एक नया मामला जिले के चांदनी बिहारपुर वनांचल क्षेत्र के माध्यमिक शाला करौटी ए से सामने आया है जहां पदस्थ एक शिक्षक का सोशल मीडिया पर शराब के नशे में स्कूल आने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। जिसे देखकर अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त शिक्षक अधिकांश दिनों में शराब पीकर ही स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करते हैं और

इसके बाद पढ़ाने की बजाय शराबखोरी में लिप्त हो जाते हैं। लगातार लापरवाही और शिक्षकीय दायित्व की अवहेलना से परेशान स्थानीय युवाओं ने बुधवार को इन्हें स्कूल समय में शराब पीते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। युवाओं ने जब शिक्षक से सवाल किए तो वे नशे की हालत में बहाने बनाते और खुद को सही साबित करने का प्रयास करते नजर आए। बताया गया कि वे ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। मौके पर ही ग्रामीणों ने पूरा घटनाक्रम वीडियो में दर्ज कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह का अनुशासनहीन व्यवहार कब तक चलता रहेगा। गांव के सरपंच गजमोहन सिंह ने बताया कि शिक्षक की शराबखोरी और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर पहले भी कई बार लिखित शिकायत की गई है। पंचायत स्तर पर पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को भी शिक्षक के व्यवहार की जानकारी है, लेकिन कार्रवाई न होने से मनोबल बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जहां बच्चे ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, वहीं शिक्षक शराब के नशे में हो तो शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित कैसे रह सकता है। अब स्थानीय लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वायरल वीडियो और लगातार की जा रही शिकायतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि एक बार फिर मामले को दबाने की कोशिश हुई, तो भविष्य में ऐसे शिक्षक और भी बेलगाम हो सकते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि शिक्षा विभाग तत्काल प्रभाव से जांच कर दोषी पाए जाने पर शिक्षक संजय सिंह के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करे।

हिंदू महासंगम का आयोजन बिश्रामपुर में आज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। हिन्दू जनजागरण समिति मण्डल बिश्रामपुर द्वारा आयोजित हिन्दू महासंगम आज 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हिंदू महासंगम कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से दशहरा मैदान केंद्रीय चिकित्सालय के सामने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। कार्यक्रम को लेकर स्वयंसेवक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों, कालोनियों और बाजारों में जाकर लोगों को आमंत्रण पत्र बांट रहे थे। हिन्दू जनजागरण समिति ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाएं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड महोत्सव आयोजित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम देवीगंज में वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थाई समिति के द्वारा जल संरक्षण विषय पर विस्तृत जानकारी दिया गया परियोजना अधिकारी श्री रॉबिंसन सुधीर कुजूर के द्वारा वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम के बारे में जल और मृदा की उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्र-

छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई साथ ही अमृत सरोवर और सिंचाई नाली के साफ सफाई में श्रमदान किया गया। इस दौरान करमा नृत्य के साथ साथ स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए जल संरक्षण पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थाई समिति के सभापति श्री बद्री यादव, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती सूरजमुनिया उइके, वाटरशेड समिति के अध्यक्ष श्री उदय भान मरकाम, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वाटरशेड परियोजना के सभी अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामीण एवं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अनियंत्रित पिकअप पलटने से दो युवक की मौत, दो घायल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर, बिहारपुर। बीती शाम ओडगी थाना क्षेत्र के ग्राम बेदमी घाट के समीप एक पिकप के अनियंत्रित होकर पलट जाने से दो युवकों की मौत हो गई है वहीं दो युवक गम्भीर रूप से आहत हुए है। बताया गया है कि रविवार की शाम बेदमी बाजार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन क्र. जे एच 03 एसी9956 से चार युवक रविवार की शाम बेदमी बाजार से सामान लेकर अपने घर मसनकी लौट रहे थे। तभी रास्ते में पिकअप का स्टेरिंग व ब्रेक फेल हो गया। नियंत्रण बिगड़ने के बाद वाहन सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार युवक दब गए। ग्रामीणों की मदद से पिकप के नीचे दबे लोगो को बाहर निकाला गया। हादसे में 25 वर्षीय जय कुमार पिता बिहारी लाल मसनकी उपरपारा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि वाहन में सवार तीन अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व 108 एंबुलेंस टीम मौके पर पहुँची। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओडगी पहुँचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सूरजपुर रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान घायल 30 वर्षीय दुर्गेश की भी मौत हो गई है। पुलिस ने मृतकों को पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। जबकि अन्य दो आहतों का उपचार किया जा रहा है। घटना से ग्राम मसनकी में शोक का वातावरण है।

पत्नी की हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के चांदनी थाना क्षेत्र के ग्राम नवाटोला में पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि 20 नवम्बर को ग्राम सरना थाना रघुनाथनगर बलरामपुर की प्रभावती काशी ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बहन के घर नवाटोला आई तो भतीजा बताया कि पिता अशोक रजक मम्मी को मारकर कुआं में डाल दिया है। 18 नवम्बर के रात्रि में उसका पिता, माँ को मार रहा था छोटा भाई मना किया तो उसको भी मारपीट किए जो घर से बाहर भागकर बाड़ी में छिपकर देख रहा था। पिता ने डण्डा व सिलबट्टा से मारपीट कर जान से मारकर कुआं में डालकर पैरा से ढक दिया। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना चांदनी में धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले में

घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने हत्या के फरार आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। थाना चांदनी पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी में लगी थी इसी बीच मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी उड़ीसा से वापस अपने घर आया है जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी अशोक रजक 39 वर्ष निवासी ग्राम नवाटोला माझापारा, थाना चांदनी को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने बताया कि खाना नहीं बनाने की बात को लेकर आवेश में आकर पत्नी की हत्या कर शव को कुआं में डालकर पैरा से ढकना स्वीकार किया। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व सिलबट्टा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन थाना प्रभारी चांदनी प्रदीप सिदार, एएसआई क्षेत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक इसित बेहरा, आरक्षक मुकेश साहू, भुनेश्वर पाटले, आलोक सिंह, मंजीत कुमार व रूपदेव राजवाड़े सक्रिय रहे।

धान खरीदी में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : भूलन

0 विधायक भूलन ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण, किसानों से चर्चा कर जानी समस्याएं 0 किसानों की मांग पर खरीदी की लिमिट बढ़वाने त्वरित फल का दिया भरोसा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां के धान खरीदी केंद्र में अब तक 370 किसानों से करीब 16 हजार क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है खरीदी केंद्र के व्यवस्थाओं का जायजा लेने सोमवार को स्थानीय विधायक भूलन सिंह मरावी पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानी।

निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि वर्तमान में केंद्र की क्रय सीमा 1538 क्विंटल प्रति दिन निर्धारित है, जो किसानों की संख्या और बढ़ते दबाव के अनुरूप कम पड़ रही है। किसानों ने विधायक के सामने लिमिट बढ़ाने की मांग रखी। इस पर विधायक मरावी ने कलेक्टर से बात कर लिमिट बढ़ाने हेतु पहल करने का भरोसा दिलाया है। किसानों ने विधायक से रकबा सुधार को लेकर भी समस्या बताई। इस

पर विधायक ने आश्वस्त किया कि राजस्व विभाग की टीम जल्द ही शिविर लगाकर सभी किसानों के रकबा संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगी, जिससे किसी किसान को धान विक्रय करने में दिक्कत न हो। विधायक भूलन ने मौके पर धान के वजन की भी जांच की। उन्होंने पाया कि हर बोरी में 40.7 किलो धान लिया जा रहा है। इस पर उन्होंने प्रबंधक मोहन राजवाड़े को किसानों की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ इसी मानक पर खरीदी जारी रखने और किसी भी प्रकार की मनमानी या लापरवाही न करने के सख्त निर्देश दिए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई तो सीधे कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रबंधक और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि खरीदी व्यवस्था सुचारू और पारदर्शी ढंग से संचालित हो, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय मे मामला क्रमांक 202512020700027

विषयः— ब—121
मामले की श्रेणीः— राजस्व
सन् :— 2025—2025

रनपुरकला प.ह.न. 00029 (हे0),
पक्षकारों का विवरण — आवेदक पक्षकार अश्विनी कुमार सिंह,
अनावेदक पक्षकार छ०ग० शासन.

ईश्तहार

आवेदक अश्विनी कुमार सिंह पिता अखिलेश सिंह निवासी ग्राम रनपुरकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम रनपुरकला स्थित भूमि खसरा नंबर 40/2, 108/11 रकबा 0.404, 1.031 हे० भूमि के द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19.12.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 05/12/2025 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०/अ—2/2025—26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम कछार को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमवती यादव पति देवतारी, जाति महकुल, निवासी ग्राम कछार, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्य एवं आधिपत्य भूमि स्थित ग्राम कछार, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 437 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि भिन्न से आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी—1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19/12/2025 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा—आपत्ति पर कोई विचार नहीं

आज दिनांक 05/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
धौरपुर

जम्मू में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुई शिक्षिका मुस्कान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पीएमश्री स्कूल अंतर्गत अध्यापन कार्य का रहे विज्ञान एवं गणित शिक्षकों का क्षमता विकास हेतु एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी में पारंगत बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के निर्देशानुसार पीएमश्री राज्य प्रभारी आशीष गौतम के साथ छत्तीसगढ़ के 151 विज्ञान शिक्षकों ने आईआईटी जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त किया। ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा संचालित पीएमश्री स्कूल जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करना और देशभर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। पीएम श्री स्कूल, अन्य स्कूलों के लिए रोल मॉडल होंगे ताकि शिक्षा में समानता और गुणवत्ता लाई जा सके जहाँ डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, लैब्स, ग्रीन स्कूल, खेल और कौशल शिक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराया जा रहा है समग्र शिक्षा

अर्थात् बच्चों का ज्ञान, कौशल, चरित्र और मूल्य आधारित विकास करना केवल परीक्षाआधारित शिक्षा से हटकर प्रयोगात्मक और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना विद्यार्थियों को समान अवसर ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी बेहतर स्कूलिंग वातावरण देना। जिसके लिए पीएम श्री स्कूल में सेवाएं प्रदान कर रहे शिक्षकों को भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षित करना आवश्यक है इसी उद्देश्य से सरगुजा संभाग से 20 पीएम श्री स्कूल्स के शिक्षकों सहित राज्यभर से 151 शिक्षकों का प्रशिक्षण आईआईटी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई है जिसमे शिक्षकों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट लैब थ्रीडी प्रिंटर, गूगल क्लासरूम, सायबर सिक्योरिटी, सायकोलाजिकल ईंपैक्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफार्म आधारित बेहतर कक्षा संचालन के तरीके सिखायें गए एवं आईआईटी लैब का अवलोकन करवाया गया। इस हेतु पीएमश्री स्कूल सूरजपुर, जयनगर, बत्रा, प्रेमनगर, कोटया, शिवप्रसादनगर, जशपुर के शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमे शिक्षक मुस्कान अग्रवाल, विशाल शर्मा, हिमांशु शर्मा, नैन्सी तिर्की, अर्चना ठाकुर, खूबचंद रजवाड़े, लोमेश सिन्हा, इसके साथ छत्तीसगढ़ के चयनित पीएमश्री विद्यालयों से शिक्षक पांच दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता प्रदान किए। सभी प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया, पाँचों दिनों में मिले मार्गदर्शन, गतिविधियों और व्यावहारिक सीख ने उनके कौशल में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जोड़ा। उन्होंने आयोजकों और प्रशिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनुभव भविष्य में उनके शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

इस आयोजन में आशीष गौतम पीएमश्री राज्य प्रभारी, सुब्बा नायडू, दिनेश चतुर्वेदी, संदीप, मुस्कान अग्रवाल, कल्पना दास, लोकनाथ, अमित, शीतल, लोमेश सिन्हा, श्वेता एवं अन्य शिक्षकों की भागीदारी रही।

समर्थन मूल्य पर मेहनत का मिल रहा उचित दाम

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी कार्य सुचारू और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिले में भी निर्बाध रूप से किसानों से धान खरीदी की जा रही है। जिले के बलरामपुर विकासखंड के झलपी ग्राम पंचायत के शिव कुमार इस वर्ष धान खरीदी केंद्र पहुंचे उन्होंने बताया कि टोकन कटाने से लेकर धान बेचने तक की प्रक्रिया बेहद आसान और सरल रही। केंद्र पर पहुंचते ही कर्मचारियों ने तुलाई कर उनका 102 बोरी धान समर्थन मूल्य पर खरीदा। वे बताते हैं कि इस वर्ष वे लगभग 330 बोरी धान बेचने वाले हैं, जिससे उन्हें अच्छी आर्थिक आय होने की उम्मीद है। शिव कुमार कहते हैं सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होने से हमें हमारी मेहनत का पूरा दाम मिलता है। इस वर्ष मिलने वाले पैसे से मैं अपने बच्चों के ब्याह

का खर्च आसानी से पूरा कर सकूंगा। उन्होंने खरीदी व्यवस्था संतोष जताया। शिवकुमार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हित में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदी पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। इससे हमें सीधा आर्थिक लाभ मिलता है और हमारी कठिन मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त होता है। धान खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार वजन-मापक, बारदाना, स्टॉक प्रबंधन, टोकन व्यवस्था और गुणवत्ता परीक्षण की सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। जिला प्रशासन भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक खरीदी केंद्र की नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि किसी भी किसान को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस वर्ष धान खरीदी ने शिव कुमार जैसे सैकड़ों किसानों के लिए न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग खोला है, बल्कि उनके सपनों को साकार करने की उम्मीद भी जगाई है।

जिले के 1044 अपात्र परिवारों का आवास होगा निरस्त, 23 तक जिपं में दावा आपत्ति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस जयवर्धन एवं सीईओ जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन व निर्देशन में शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास ग्रामीण की निरंतर समीक्षा की जा रही है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य किए जा रहे है। योजनांतर्गत एसईसीसी 2011 से तैयार स्थाई प्रतिक्षा सूची तथा आवास प्लस 2018 से तैयार स्थाई प्रतिक्षा सूची में पाए गए, समस्त अपात्र परिवारों के नामों को पोर्टल से विलोपित करने की कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी एसईसीसी से तैयार प्रतिक्षा सूची से 2456 अपात्र परिवारों के नामों को जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दावा आपत्ति आमंत्रित कराए गए थे। जिसमें कुल 28 आपत्ति प्राप्त हुए है। उक्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त जिले के समस्त जनपद पंचायतों से एसईसीसी 2011 से तैयार प्रतीक्षा सूची अंतर्गत 461 एवं आवास प्लस 2018 से तैयार प्रतीक्षा सूची अंतर्गत 583 परिवारों का भिन्न भिन्न कारणों (मृत, कोई उत्तराधिकारी नहीं, स्थायी पलायन, इत्यादि) से अपात्र की जानकारी ग्राम सभा एवं जनपद स्तर से सत्यापन पश्चात् जिले को पुन: प्राप्त हुआ है। उक्त दोनों सूचियों को हितग्राहिवार अपात्र एवं अपात्र के कारण सहित जानकारी तैयार कर जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जिसके लिए www.surajpur.nic.in पर विस्तृत जानकारी के लिए अवलोकन कर सकते है। यह सूची जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल, जनपद पंचायत के सूचना पटल एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। जिस किसी को भी उक्त सूची में आपत्ति है तो 23 दिसंबर कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक जिला पंचायत में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करा सकते है। किसी भी प्रकार के समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9244049285 पर सीधे संपर्क कर सकते है।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 9713108088 8719000259

कोरिया फ्रंटलाइन

तीन ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 25 लाख के निर्माण कार्यों का स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमिपूजन

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। खड़गवां विकासखण्ड के तीन ग्राम पंचायतों में लगभग 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। बीते रविवार को खड़गवां जनपद पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों ने नई रफ्तार पकड़ी। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत तीन ग्राम पंचायतों—खड़गवां, मेंड्री और उधनापुर—में सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्यों का भूमिपूजन स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हाथों संपन्न हुआ। इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार रुपए है।मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 41.72 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क तथा नाली निर्माण होंगे। ग्राम पंचायत खड़गवां में प्राथमिक शाला जनकपुर से महेंद्र के घर जनकपुर तक। ग्राम पंचायत मेंड्री में मेंड्री मार्ग से धवईपारा पहुंच मार्ग तक। ग्राम पंचायत उधनापुर में मुख्य मार्ग दक्षिणपारा से नवानगर उधनापुर गौठान तक। इन निर्माण कार्यों से ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा, आवागमन में सुगमता और बरसात में जल निकासी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।

हर घर एक गाय पालन की अपील

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा गौवंश की बढ़ती संख्या पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने ग्रामीणों से महत्वपूर्ण अपील की कि यदि हर घर एक गाय पालन का संकल्प ले लें, तो आवारा गायों की समस्या खत्म होगी और आपको खेतों व बारी-बगीचे के लिए भरपूर जैविक खाद भी मिलेगा। मैं स्वयं अपने घर एक मुड़ा गाय पालता हूँ। इस अपील पर ग्रामीणों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

आप लोगों से मिलने का बहाना है भूमिपूजन: श्री जायसवाल

आप लोगों से मिलने का बहाना है भूमिपूजन: मंत्री श्री जायसवाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मैं यहां भूमिपूजन करने जरूर आया हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि यह आप सभी से मिलने का एक बहाना है। आप लोगों का समर्थन, विश्वास और विकास की आकांक्षा मुझे लगातार कार्य के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने ग्राम पंचायत के उन वरिष्ठ बुजुर्गों का भी स्मरण किया जिन्होंने 25 वर्ष पहले पंचायत निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री साय पूरे प्रदेश में साय-साय काम कर रहे हैं यानि सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से कितनी महिलाओं को राहत मिली है, इसकी जानकारी भी क्षेत्र में ली गई। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

पीड़ित के परिजन को 16 हजार की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी। प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(ग)(1) के अंतर्गत तहसील मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत हर्रा, निवासी ललित कुमार साहू की आकाशीय बिजली गाज गिरने से हुई दुर्घटना के पश्चात उनके वारिस श्री उर्दयाली को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

नव-निर्वाचित सरपंचों को जल जीवन मिशन की बारीकियों से दिया गया प्रशिक्षण

एमसीबी। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र भरतपुर में नव-निर्वाचित सरपंचों के लिए आयोजित 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन मिशन पर केंद्रित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र संपन्न हुआ। इस सत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशेषज्ञों ने जल जीवन मिशन योजना के संचालन और संधारण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी राजपत्र में वर्णित प्रावधानों की जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली हस्तांतरण प्रक्रिया, पेयजल आपूर्ति प्रणाली के प्रमाणीकरण एवं सत्यापन की अनिवार्यताओं को सरल और चरणबद्ध तरीके से समझाया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने जल गुणवत्ता परीक्षण की अनिवार्यता, पेयजल व्यवस्था के नियमित रख-रखाव, समुदाय की सहभागिता और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी विस्तृत चर्चा की। प्रतिभागियों को बताया गया कि जल जीवन मिशन की सफलता न केवल तकनीकी प्रणाली के सुचारू संचालन पर निर्भर करती है, बल्कि ग्राम स्तर पर जागरूकता, पारदर्शिता और समुदाय के सहयोग पर भी आधारित है। सत्र के दौरान उपस्थित सभी सरपंचों ने प्रशिक्षण के प्रति विशेष उत्साह प्रदर्शित किया और प्राप्त ज्ञान को अपने-अपने ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने माना कि जल जीवन मिशन से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक समझ सामाजिक विकास एवं बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।

झगड़ाखांड नगर पंचायत में विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। झगड़ाखांड नगर पंचायत में विकास कार्यों की उपेक्षा के विरोध में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हेमलता कोमल कुमार ने सोमवार को अपने समर्थकों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर से सौजन्य मुलाकात कर एक शिकायत पत्र सौंपा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों के विकास कार्यों के लिए शासन से लगभग 3 करोड़ रुपये स्वीकृत होने हैं, जिनका समान रूप से उपयोग होना चाहिए। लेकिन नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9, 5 और 6—जो एसटी, एससी एवं ओबीसी महिला आरक्षित वार्ड हैं । वहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी और उनके सहयोगी कर्मचारियों द्वारा विकास कार्यों में गंभीर लापरवाही और भेदभाव बरता जा रहा है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही सीएमओ को फोन कर प्रभावित वार्डों में आवश्यक विकास कार्य तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। श्रीमती हेमलता ने चेतावनी दी कि यदि भेदभावपूर्ण स्थिति बनी रही, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर तीव्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मंडलम अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, रामगोपाल यादव, राजकुमार यादव, राधे मिश्रा, पूर्व पार्षद राकेश यादव, कोमल कांत, केडी, शेषमणि कोल, संजय यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

खरीफ विपणन 2025-26 किसान सूर्य प्रताप सिंह का अनुभव बना मिसाल

एमसीबी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 इस बार किसानों के लिए उम्मीद, विश्वास और बेहतर व्यवस्था का नया अध्याय लेकर आया है। ग्राम मेन्ड्रा के किसान सूर्यप्रताप सिंह का सकारात्मक अनुभव इसका प्रमाण है, जिन्होंने कोड़ा उपार्जन केंद्र में धान बेचने के दौरान पूरी प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी और किसान-सम्मान की भावना से भरपूर पाया। सूर्यप्रताप सिंह बताते हैं कि उपार्जन केंद्र पहुंचते ही उन्हें वातावरण पिछले वर्षों से बिल्कुल अलग महसूस हुआ। केंद्र परिसर साफ-सुथरा था, किसानों के लिए सुव्यवस्थित कतारें, पर्याप्त बारदाना, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और कर्मचारियों की तत्परता ने उन्हें प्रभावित किया। वे कहते हैं कि जहां पहले खरीदी के दौरान अव्यवस्था, भीड़ और समय की बर्बादी जैसी दिक्कतें होती थीं, वहीं इस बार संपूर्ण प्रक्रिया सुगम, समयबद्ध और पारदर्शी रही। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह रहा कि उनका टोकन ऑनलाइन नहीं कटा था, फिर भी केंद्र में मौजूद अधिकारियों ने बिना किसी परेशानी के उनकी खरीदी की प्रक्रिया पूर्ण कराई। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा घोषित 3100 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी सीमा को किसान हित में बड़ा कदम बताया। उनके अनुसार यह निर्णय किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उनके परिश्रम का सही मूल्य प्रदान करता है। केंद्र की व्यवस्था से प्रभावित सूर्य प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष की खरीदी व्यवस्था ने साबित कर दिया है कि सरकार वास्तव में किसान-केंद्रित फैसले ले रही है।

नगर पालिका ने चलाया आवारा कुत्तों का धड़पकड़ अभियान

सीएमओ संजय दुबे के नेतृत्व में कार्रवाई, पकड़े गए कुत्तों की होगी नसबंदी

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद देशभर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर नगर निकाय सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया। यह कार्रवाई नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय दुबे के नेतृत्व में की गई।

पालिका टीम द्वारा पकड़े गए कुत्तों को पशुपालन विभाग के सहयोग से सुरक्षित तरीके से ले जाया जा रहा है, जहाँ उनकी नसबंदी, टीकाकरण और आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य शहर में बढ़ रहे कुत्तों की अनियंत्रित संख्या को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सीएमओ श्री दुबे ने बताया कि आक्रामक और हमलावर स्वभाव के कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगा, ताकि शहर में कुत्तों से जुड़ी दुर्घटनाओं और रेबीज संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी आवारा कुत्ते को अपने स्तर पर पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा प्रयास खतरनाक हो सकता है। बच्चों को विशेष रूप से ऐसे कुत्तों से दूर रखने की सलाह दी गई है। सीएमओ ने यह भी कहा कि यदि किसी नागरिक व बच्चों को कुत्ता काट ले, तो वे तुरंत अस्पताल जाकर जांच और उपचार अवश्य कराएँ, ताकि संक्रमण की आशंका को समय रहते रोका जा सके।

नगर निरीक्षक ने होटल व ढाबा संचालकों की ली क्लास

कहा होटल व ढावों में बिकी अवैध शराब तो होगी कड़ी कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के निर्देश और पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर श्रीमती रत्ना सिंह के मार्गदर्शन में सोमवार को सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपेश सैनी ने शहर क्षेत्र के होटल और ढाबा संचालकों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की।

बैठक में सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपेश सैनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी होटल या ढाबा में अवैध रूप से शराब बेचना, संग्रहित करना अथवा ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां ना केवल आबकारी अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि इससे शांति व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए पुलिस इस पर किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। निरीक्षक दीपेश सैनी ने सभी संचालकों को कानून का पालन करने की शपथ दिलाई और कहा कि पुलिस समय समय पर होटल-ढाबों की जांच करेगी। यदि किसी भी संचालक के यहां नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना शामिल है। इसके साथ ही बैठक में होटल ढाबा संचालकों को निर्देश दिये गये कि वे अपने परिसरों में असामाजिक तत्वों को पनपने ना दें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें और होटल लाज में ठहरने वाले व्यक्तियों का सही रिकॉर्ड रखें। निरीक्षक सैनी ने कहा कि पुलिस और नागरिकों के आपसी सहयोग से ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सौहार्द्र बनाए रखा जा सकता है। बैठक के दौरान पुलिस टीम ने संचालकों से यातायात नियमों, नशा मुक्ति, शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के पालन में सक्रिय सहयोग की अपील की। उपस्थित संचालकों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है।

सचिव संरपच के मिली भगत से भारी वित्तीय अनियमितता, सूचना पटल निर्माण स्थल से गायब

ग्राम पंचायत उज्ञांव के स्कूल के सामने सी सी रोड निर्माण कार्य का मामला

छ.ग.फ्रंटलाइन

सोनहत। जनपद पंचायत सोनहत से चालीस किलोमीटर दुरी पर उज्ञांव पंचायत भवन के स्कूल पारा में सी सी रोड निर्माण कार्य जोरों पर है मजदुरो से न कराकर मशीन से काम करया जा रहा है एवं मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है गिट्टी ढालने के बाद ऊपर से मजदूर से तगाड़ी में सीमेंट घोलकर ऊपर में लेप कर रहे हैं नीव फाउंडेशन भी नहीं खोदी गई है न तो नीचे रेत डाली जा रही है और पन्नी भी नहीं लगाई जा रही है इस्टीमेट में सीमेंट 53 ग्रेड का लगना है जबकि लग रहा है 46 ग्रेड रीवा राखड़ का लग रहा है ढलाई किये स्थान में तराई का नामों निशान नहीं है सुचना पटल भी नहीं लगा है जबकि अब कार्य पूर्ण होने की कगार पर है सोनहत विकास खंड में प्रथा स्वरूप काम होने के बाद सुचना पटल लगाई जाती ग्रामीणों का कहना है कि सीमेंट साईड में दिखावा के लिए कुछ रखा रहता है लग कुछ रहा है और सीमेंट का मात्रा भी बहुत ही कम मात्रा में डाला जा रहा है रोड कुछ ही दिनों में टुट जायेगी प्रत्यक्ष उपस्थित ग्रामीणों का कहना है कि संरपच की मिली भगत से मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है नींव की खुदाई नहीं होने के कारण काफी कम मोटाई रखी जा रही है ग्रामीणों का कहना है कि हमारा विकास नहीं विनाश हो रहा है उनका कहना है कि काम तुरंत रोका जाये एवं एक तकनीकी जांच दल मौके पर भेजकर जांच कराई जानी चाहिए सी सी रोड निर्माण का मतलब सीमेंट और कंक्रीट से सड़क बनाना जो डामरीकृत सड़कों की तुलना में अधिक टिकाऊ और मजबूत होती है साइड तैयारी सड़क बनाने की जगह को नीव खोदना ताकि कंक्रीट के लिए मजबूत आधार मिल सके सुढ़ढीकरण कंक्रीट डालना क्योरिग फिनिशिंग सभी प्रकार की सड़कों में से सबसे मजबूत और टिकाऊ सड़क बनती है सी सी रोड अगर मानक रूप में बनी है तब ठोस एवं मजबूत होती हैं जहां सतह सीमेंट कांक्रीट की एक ठोस परत से बनी होती है ऐसी सड़कों को कठोर फुटपाथ भी कहा जाता है यह सड़क अवसंरचना के लिए एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला विकल्प है। इस संबंध में एस डि ओ आर ई एस विभाग सोनहत नंदनी दुबे ने बताया कि निर्माण कार्य में समझौता नहीं की जायेगी इसकी निरीक्षण तत्काल करवाते हैं।

लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु जागरूकता अभियान

बैकुंठपुर। कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के दिशा-निर्देश तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज बैकुंठपुर स्थित चाइल्ड लाइन कार्यालय में स्वास्थ्य मितानिनों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताओं को लिंग आधारित हिंसा, उससे जुड़ी कानूनी दंड प्रक्रिया, हिंसा के कारण, तथा रोकथाम के व्यावहारिक उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उद्देश्य यह रहा कि मितानिनें समुदाय में महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के साथ होने वाली हिंसा की पहचान कर सकें तथा पीड़ितों को उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकें।

सामुदायिक शौचालय उज्ञांव का निर्माण कार्य में उपयोग हो रहा घटिया सामग्री

■ खुलेआम संरपच सचिव उप यंत्री के द्वारा गला हुआ ईट का उपयोग निर्माण कार्य में की जा रही

छ.ग.फ्रंटलाइन

सोनहत। विकास खंड सोनहत के उज्ञांव पंचायत भवन के बगल में सामुदायिक शौचालय निर्माण संरपच सचिव के द्वारा कराई जा रही है जिसमें अपने खास रिसतेदार का गला हुआ ईट का उपयोग निर्माण कार्य में खपाई जा रही है जो ईटा तीन टुकड़ों में बट चुका है वह भी जोड़ाई में खपाई जा रही है ग्रामीणों का कहना है कि संरपच सचिव बोलते हैं कि हम बनाकर देगे आप लोग क्यों परेशान हो वही पर सीमेंट भी घटिया किस्म का लगाया जा रहा है एवं मानक के हिसाब से नहीं मिलाया जा रहा है ग्रामीणों ने बताया कि नींव भी बहुत कम खोदी गई है जिसमें दीवार कुछ ही दिनों में दरार पड़ जायेगी एवं शौचालय उपयोग लायक नहीं रह जायेगी ग्रामीणों का कहना है कि संरपच सचिव कभी भी ग्राम सभा में जन हितकारी की जानकारी नहीं देते हैं न तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में होती है न कभी लेखा जोखा देते हैं संरपच सचिव की मनमानी चरम सीमा पर है ग्रामीणों का बात कभी भी नहीं सुनते हैं सामुदायिक शौचालय में भी वित्तीय अनियमितता अपनाई जा रही है यह एक साझा स्वच्छता सुविधा है मोहल्ले गांव के लोग द्वारा उपयोग के लिए बनाई जाती है इसका मुख्य उद्देश्य खुलें में शौच को रोकना है जिससे स्वच्छता और बीमारियों से बचाव हो सके स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच ओ डि एफ की समस्या को खत्म करना इसमें नियमित सफाई साबुन फिनायल आदि की व्यवस्था करना शामिल है सामुदायिक शौचालय एक सुविधा है एक सामाजिक पहल है जो स्वच्छता सम्मान सुरक्षा प्रदान करती है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन नं. 497001 से मुद्रित व महलपारा बैकुण्ठपुर से प्रकाशित। संपादक- कमलेश शर्मा